RESOLUTION *RE* APPOINTMENT OF A PARLIAMENTRY COMMITTEE TO ENQUIRE INTO AGRICULTURAL COOPERATIVES AND SUGGEST MEASURES FOR STRENGTHENING THEM—*continued.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The Resolution moved by Shri Sri Rama Reddy is before the House. Shri Raghunatha Reddy.

SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, the Resolution that has been moved by my hon. friend Shri Sri Rama Reddy is of a very timely character. It deserves sufficient attention not only by this House but also by the Government and also members of the public. Mr. Vice-Chairman, the cooperative movement relating to credit is intimately connected with production in the agricultural sector. Those who have read the various reports on cooperative movement in relation to credit surveys, must have come across and known that poor agriculturists are not in a position to get proper credit for the purpose of utilising it either for manure or for tiding over the period that is called the period of distress sales, after their harvesting is done. For the purpose of creating stability in the agricultural sector in the context of production, it is high time that Shri Sri Rama Reddy's Resolution is given sufficient consideration and considered thought by those who are at the helm of affairs so that the ideas expressed here in this Resolution may find fulfilment in actual implementation.

Mr. Vice-Chairman, the idea of the entire cooperative movement might sound, to some extent, a reformist one. That is so, because the cooperative movement is one of the many steps or one of the many means by which democratic socialism in this country may be based on the triumphs of democracy and not on the tyranny of dictatorship. That is the essence of democratic socialism or in other words Socialism is to be achieved in this country on the triumphs of democracy and not on the tryanny of dictatorship. To achieve this end, as the late Prime Minister stated quite a number of times, the cooperative movement is one of the steps that has to be taken in this context for the purpose of achieving socialism, for the purpose of working out a social change. So when dealing with the agricultural sector, it is absolutely necessary to concentrate one's attention on the question of production, because production is the essence of any developing economy, an economy developing towards betterment, towards socialism. So the various defects pointed out by my hon. friend in relation to land mortgage banks, in relation to credit facilities available to the agriculturists, in relation to the marketing of their produce and in relation to various other credit cooperative societies, will have to be taken into due consideration by all those who have the interest of the country at heart.

Mr. Vice-Chairman, when we read.. the autobiography of Pandit Jawaharlal Nehru, we are struck by the variouns steps that he contemplated and by his concept of socialism or classless society. When referring to this subject, he writes in his autbiography:

> "Our final aim can only be a classless society, with equal economic justice and opportunities for all a society organised on a planned basis for the raising of mankind to higher material and cultural levels, to cultivate the spiritual values of co-operation, unselfishness and the spirit of service and the desire to do the right, goodwill and love, ultimately a world order. Everything that comes in the way will have to be removed gently if possible, forcibly if necessary."

He concedes that in certain very inordinate circumstances force may perhaps have to be used. But he is one of those persons who had a passionate belief in socialism by democratic means and by peaceful persua-

[Shri K. V. Rughunatha Reddy.]

sion. So Mr. Vice-Chairman, in order to create that psychology of willingness, in order to create that objective idealism the cooperative movement will have to be encouraged because through the pursuit of the cooperative movement, people are brought together and if it is properly organised then the ideals of self-sacrifice, of unity of thought and of action, could be inculcated in human beings so that the appeal on which the edifice of socialism will be built will be the appeal to the goodness that is in man and not to the conflicts that are there in human nature. The entire edifice of socialism will have to be built up on the development of the personality of man and so the appeal will have to be an appeal to the good in human nature and not to the conflicts, not to the misery, not to the psychological conundrums that confront human thinking. So in this context the cooperative movement in relation to production will have to receive sufficient attention.

In the introductory chapter in the Third Five Year Plan we have the objectives set out and the steps necessary to achieve this classless society through socialism and one of the suggestions is the use of the cooperative method and if necessary even collectivisation. The first step in order to reach the goal of socialism is that of collective farming and the very first step to be undertaken in this context is the development of the cooperative movement, because if we cannot bring people even on a small scale to cooperate with each other for achieving certain objectives, it would be very difficult to bring human beings to a state of collectivisation. So the cooperative movement is one of the earliest steps that will have to be taken for the purpose of developing this country and putting it on the road to economic growth and peaceful persuasion so that the good in man may triumph over the evils of society. In this context, this Resolution of my hon. friend is very much to be welcomed and I strongly support it. I do not want to take up the time of the House now, because last year when I moved my Resolution on cooperative movement I had expressed myself sufficiently on this subject and I thank you very much for giving the opportunity.

श्री देवकी नन्दन नारायण (महाराष्ट्र): आदरणीया उपसभापति जी, मैं उस राज्य से आ रहा हूं जहां कोआपरेटिव सोसायटीज़ काफी बड़ी हैं और फैली हुई हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें काफी कामयाबी मिली है। सिर्फ एग्रीकल्चरल क्रैडिट सोसायटीज़ ही नहीं, बल्कि मल्टी-परपज़ सोसायटीज, मार्केटिंग सोसायटीज, कंज्युमर्स सोसायटीज़, प्रोसेसिंग सोसाइटीज़ वहां काफी हैं और यहां तक कि कोआपरेटिव शुगर मिल्स महाराष्ट्र में जितनी हैं, उतनी शायद और प्रदेश में नहीं हैं और वे बहुत मुनाफे से चल रही हैं, नुकसान से नहीं। साथ साथ जिनिंग फैक्ट्रीज कोआपरेटिव बेसिस पर चल रही हैं और अब कोआपरेटिव बेसिस पर स्पिनिंग मिल्स निकलने को है। मैं जिस शहर से आता हूं उस शहर में एक स्पिनिंग मिल्स इस बेसिस पर निकलने को है। मेरे यहां से १५ मील पर भुसावल है। वहां एक कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स तैयार हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कहना कि हर जगह कोआपरेटिव मूवमेंट फेल हुआ है, नाकामयाब हुआ है, यह गलत है। हां, मैं यह मानता हूं कि जिस तरह आज के समाज में, आज के व्यवहार में, आज के व्यापार में गड़बड़ी है उसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज़ में भी गड़बड़ी हो सकती है। और है। मिसएप्रोप्रिएशन है, बेईमानी है—यह मैं मानता हूं। परसों यहां सवाल पूछा गया कि बहुत सी जगह बोगस कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। जहां तक बोगस कोआपरेटिव सोसाइटीज़ का सवाल है मैं तो कहूंगा कि यह बोगस कोआपरेटिव सोसाइटीज़ की जिम्मेदारी आफिसर्स के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। आप जानते हैं कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट जो है वह स्टेट सब्जैक्ट है और इसकी जिम्मे-

दारी अगर किसी पर डाली जा सकती है तो वह स्टेट आफिसर्स पर डाली जा सकती है। जो रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और उन के मातहत जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं वह इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि देश में प्लानिंग के साथ एक नई टार्गेट की बीमारी बढ़ गई है।

हमें यह टारगेट पूरा करना है, इस टारगेट को पहुंचना है। तो को० आफिसर्स किसी तरह से अपनी संख्या पूरी करने की कोशिश करते हैं—मुझे तो इस साल में इतनी सोसाइटीज बनानी ही हैं और इसलिये वह बनाता है। वह यह नहीं सोचता है कि यह सोसाइटी किस तरह चल सकती है, इन सोसाइटीज के काम करने वाले ईमानदार हैं या नहीं, इस सोसाइटी के पास खुद का पैसा है या नहीं। परन्तु उसे तो टारगेट पूरा करना होता है इसलिये वह सोसाइटियां खड़ी कर देता है, इसलिए कुछ सोसायटीज बोगस बन जाती हैं और बोगस होने के कारण और खराबियां पैदा होती हैं। इसके जिम्मेदार सोसाइटीज को पैदा करने वाले आफिसर्स हैं। कोआपरेटिव सोसाइटी तो एक ऐसी चीज है जिसका अत्युत्तम उपयोग भी हो सकता है और उससे बुराई भी पैदा हो सकती है। दुनिया में हर एक काम में ऐसा हो सकता है, चाकू से आप हाथ भी काट सकते हैं, उसका बहुत सदुपयोग भी हो सकता है। उसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज की बात है। इसलिये यह कह देना कि सब सोसाइटियां बोगस हैं, वे फेल हो गई हैं यह मैं नहीं मानता। मुझे अपने जिले का, प्रान्त का अनुभव है जहां ये बहुत कामयाब हुई हैं। मेरे जिले में शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी या मल्टी परपज़ सोसाइटी या सर्विस सोसाइटी नहीं है, करीब १३०० सोसाइटीज हैं। हमारे जिले में एक ऐसा कोआपरेटिव बैंक है कि शायद उतना अच्छा कोआपरेटिव बैंक हिन्दुस्तान में कहीं न होगा, जिसका कई करोड का लेनदेन होता है, उसमें तीन साढ़े तीन करोड़ रु० तक डिपाजिट्स हैं। यह मैं नहीं कहना चाहता कि बिलकुल कहीं बुराइयां नहीं हैं। बुराइयां होंती हैं परन्तु जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वह यह है कि मैंने अपने प्रदेश में देखा है, अपने जिले में देखा है कि सोसाइटियों की संख्या बढ़ रही है परन्तु सहकार कम होता जा रहा।

श्री डाह्याभाई व० पटेल (गुजरात): दराज की कोआपरेटिव सोसाइटी हुई या नहीं?

श्री देवकीनन्दन नारायण: हां, आप भी उसमें शामिल हैं क्योंकि गुजरात में भी वही हालत है जो और जगह है। आप यह न समझें कि बुराई की मोनोपोली किसी एक प्रदेश की है और सिवाय गुजरात के सब में बुराइयां हैं।

श्री डाह्याभाई व० पटेल: सब जगह कांग्रसमेन भरे हैं कोआपरेटिव सोसाइटीज में।

श्रीदेवकीनन्दन नारायण: वह मैं जानता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बुराई सब जगह कम या ज्यादा होती ही है परन्तु सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैं करता आया हूं वह यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटियों की तादाद तो बढ़ रही है परन्तु कोआपरेशन उसके साथ नहीं बढ़ रहा है। इसको हमें सोचना चाहिये, गवर्नमेंन्ट को भी यह देखना चाहिये, कि यह क्या बात है कि सोसाइटियां बढ़ लेकिन सहकार न बढ़ें। कहने को कहा जाता है, जब सहकार दिन मनाया जाता है, कि हम बढ़ते हुए जा रहे हैं और "बिना सहकार नहीं उद्धार"। परन्तु सहकार कहां है मैंने यह भी देखा है कि जिस तरह पंचायतों की वजह से गांवों में झगड़ों पैदा हुए हैं, सोसाइटियों से कम झगड़े नहीं पैदा हुए। सोसाइटियों के कारण गांवों में गुट पैदा हो गये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि सोसाइटियों में यह जो इलैक्शन का तरीका आपने रखा है क्या आप उसको बदल नही सकते। उसको बदलिए। नतीजा यह हो रहा है कि जिस

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

तरह से पार्लियामेन्ट के इलैक्शन्स में म्यूनिसिपैलिटियों के इलैक्शन्स में हजारों रुपया खर्च होता है उसी तरह से मैंने देखा है कि गांवों में कोआपरेटिव सोसाइटीज के इलैक्शन में हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं और जहां खर्च होगा वहां कम या अधिक बेईमानी तो आएगी ही—खर्चे के साथ बेईमानी लगी हुई है। इसलिये मेरा कहना है कि जहां कोआपरेशन से काम होना है, जहां सहकार से काम होता है, जहां प्रेम से मोहब्बत से काम होना चाहिये, जहां मेल मिलाप से काम होना चाहिये, और सहकार का मतलब ही क्या है म्यूचअल हेल्प, वहां इलैक्शन बाज़ी जो दाखिल हो गई है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। कोआपरेटिव सोसाइटीज में इलैक्शन जो होता है वह हर साल होता है, और प्रान्तों में क्या होता है मुझे पता नहीं,पर मेरे प्रान्त में हर साल पंचायतों या विधान सभा के इलैक्शन तीन चार या पांच साल बाद होते हैं—यह इलैक्शन भीषण बीमारी है। हर साल के इलैक्शनों के कारण काम बहुत कम हो पाता है, चार छः महीने इलैक्शन में ही चले जाते हैं और खर्चा होने के साथ आपस में झगड़े भी होते हैं। इस वजह से बहुत कम काम हो पाता है इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप इन इलैक्शन्स को तीन, चार या पांच वर्ष के लिये क्यों नही कर देते हैं? और जगह जहां चुनावों में लाखों रुपये खर्च होते हैं वहां इलैक्शन चार, पांच वर्ष के बाद हो और कोआपरेटिव्ह सोसाइटीज का इलैक्शन एक वर्ष बाद हो। यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई।

दूसरी बात जो खटकती है वह यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज का लाभ अधिक से अधिक ऊपर के तबके को होता है, वीकर सैक्शन को बहुत कम पहुंचता है। मैंने गांवों में क्रेडिट सोसाइटीज में देखा है, मल्टी परपज सोसाइटियों में देखा है, कन्ज्यूमर सोसाइटियों में देखा है, मारकेटिंग सोसाइटीज की तो बात ही क्या है, कि उनका लाभ बड़े लोगों को हुआ करता है, कहने को कोआपरेटिव सोसाइटीज खास करके उनके लिये पैदा हुई जो ग़रीब हैं, जो दबे हुए हैं, जिनके पास बहुत कम पूंजी है। उनकी भलाई के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज का जन्म हुआ। परन्तु आज देखा यह जाता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज से लाभ पहुंचता है तो ऊपर वाले तबके को पहुंचता है, बड़ी खेती वाले किसान को पहुंचता है, छोटे और गरीब लोगों को नहीं पहुंचता। दूसरी बात यह है कि गांवों में जो आर्टीजन्स हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, छोटे छोटे रोजगार वाले हैं, चमार हैं, धोबी हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, उनको आज तक कोआपरेटिव सोसाइटीज से कितना फायदा पहुंचा है? क्योंकि हर एकगांव में दो कुम्हार होंगे, दो लुहार होंगे, दो सुनार होंगे। यह कहा गया कि सरविस सोसाइटीज को, गांव में रहने वाले, हर एक को, कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बनाना चाहिए लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कहीं भी इस तरह आप सोसाइटीज कायम कर सके हैं। कहीं हुई हों तो मैं जानना चाहूंगा। सरविस सोसाइटीज का पहला मतलब यह था और नागपुर कांग्रेस प्रस्ताव का मतलब भी यही था कि गांव में रहने वाला हर एक फेमिली का एक मेम्बर उसमें शेयरहोल्डर हो या मेम्बर बने, परन्तु गरीबों को, खास कर गांवों में रहने वाले आर्टीजन्स को मौका नहीं मिलता। सोसाइटियों का मेम्बर बनने का और न उनको कोई लाभ मिलता है और न वे आर्टीजन्स अपनी अलग सोसाइटी बना सकते हैं। इसलिये उनको किस तरह सोसाइटी का लाभ पहुंचाया जा सकता है, यह सोचना चाहिये।

श्री लोकनाथ मिश्र : ये कांग्रेस वाले रास्ते में सब रोक लेते हैं।

श्री देवकीनन्दन नारायण : आपसे तो बाहर बातें हो सकती हैं।

SHRI LOKANATH MISRA: Instead of the benefits of the co-operative society flowing into the masses, to the

farmers, they take advantage of it. The Congress workers in the villages get all the advantages.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: You people also take full advantage wherever you can. This is human nature. Why do you bother so much about it? उसमें कोई फर्क नहीं पाया जात और यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है ।

श्री सी० डी० पांडे (उत्तर प्रदेश) : बेईमानी सब में हैं ।

श्री देवकीनन्दन नारायण : बेईमानी तो कम या अधिक सब में है । और देखा जाय तो अभी तक कोई बैरोमीटर पैदा नहीं हुआ, यदि पैदा हो गया होता तो मैं स्वतन्त्र पार्टी वालों को दिखला सकता कि उनमें कुछ कम बेईमानी नहीं है ।

श्री चन्द्र शेखर : (उत्तर प्रदेश) : आपने यह खुद कहा है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P BHARGAVA): Please avoid cross talk. Let him continue.

श्री डाह्याभाई व० पटेल : थोड़ा नासिक की, दराज की बात कह दीजिए ।

श्री देवकीनन्दन नारायण : आज हमारे देश में जो छोटे किसान हैं जिनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है वे ४२ टका हैं । ढाई एकड़ से कम वाले लैण्ड होल्डर्स की संख्या ४२ टका है और ढाई से पांच एकड़ वालों की संख्या है २२ टका । इस तरह आप देखेंगे कि जिनके पास आधा एकड़, एक एकड़, डेढ़ एकड़, ढाई एकड़ ऐसी जमीन है, ऐसे लैण्ड होल्डर्स हमारे यहां ६२ टका हैं । उनको आप किस तरह से फायदा पहुंचाना चाहते हैं । यह सवाल तब सामने होता है जब फार्मिंग सोसाइटीज़ का सवाल आता है । आज तक हमने बहुत से गांवों में देखा है कि हम क्रेडिट सोसाइटीज़ खड़ी करते हैं, मल्टी परपज सोसाइटी खड़ी करते हैं, मारकेटिंग सोसाइटी के लिये भी तैयार हो जाते हैं, परन्तु फार्मिंग सोसाइटी के लिये क्यों नहीं तैयार होता है किसान, इसको आपको समझना चाहिये, खास कर ऐसे किसानों के बारे में जिनके पास एक एकड़, आधा एकड़ या डेढ़ एकड़ जमीन है । महाराष्ट्र में मैंने यह देखा है कि पुराने वक्त में जो जमीन इनाम में मिली हुई है, खास करके महार लोगों को जमीनें इनाम मिली हुई हैं, आधा एकड़, पाव एकड़ जो भी हो, वह बेचारा अपनी जमीन कर नहीं सकता । यह भी नहीं हो सकता कि किसी को उठा दें या किसी को बेच दें । उनको इसके लिये तैयार करिये, उनकी मदद करिये कि वे अपनी फार्मिंग सोसाइटी बनावें । परन्तु उनको तो मदद पहुंचाई नहीं जाती जिनको कि उसकी आवश्यकता है और उनकी सहकारी फार्मिंग सोसाइटी बन नहीं पाती है । उनकी ओर जितना ध्यान आफिसर्स को देना चाहिये उतना वह भी नहीं देते और बहुतों के पास जमीन वैसे ही पड़ी रहती है, कोई उसको जोतता नहीं । तो मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि आपको यह कोशिश करनी चाहिये कि जिनके पास छोटी जमीनें, आधी एकड़ है, एक एकड़ है, डेढ़ एकड़ है, ऐसे किसानों की, लैण्ड होल्डर्स की फार्मिंग सोसाइटी बनाई जानी चाहिये । इस तरह की सोसाइटियां तब ही बन सकती हैं जब सरकार उनको पूरी तरह से मदद पहुंचाये और उनको पूरी मदद मिले । इस तरह की सोसाइटियों को क्रैडिट मिलना चाहिये और सिर्फ क्रैडिट पैसे का ही नहीं मिलना चाहिये बल्कि बैल मिलने चाहियें, खाद मिलनी चाहिये, बीज मिलना चाहिये और सब तरह से उनको मदद मिलनी चाहिये । इतना ही नहीं, उन्हें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मिलना चाहिये ताकि वे अपनी सोसाइटियों को अच्छी तरह से चला सकें ।

आज देश में जो फार्मिंग सोसाइटियां बन रही हैं वे बड़े तबके की बात है और इसी वजह से अधिक सोसाइटियां नहीं बन पातीं

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

हैं । प्रस्तावक महोदय ने फार्मिंग सोसाइटियों के सम्बन्ध में यह कहा कि वह बढ़ नहीं रही है, कामयाब नहीं हो रही हैं, तो उसका कारण यह है कि इस तरह की जितनी भी सोसाइटियां पैदा हुई हैं वे किसी और मकसद से पैदा हुई हैं । जिस तबके में इस तरह की सोसाइटियां पैदा होनी चाहियें थीं वहां नहीं हुईं । गरीबों के लिए फार्मिंग सोसाइटियां होनी चाहियें थीं लेकिन वे नहीं बन रही हैं क्योंकि इन सोसाइटियों को सरकार की ओर से जितनी मदद मिलनी चाहिये, जितना उत्साह मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है । इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं ।

प्रस्तावक महोदय ने अपने प्रस्ताव में यह कहा है कि इस काम के लिए एक कमेटी कायम की जानी चाहिये । मेरा तजुर्बा यह है कि अगर किसी काम को आगे के लिए धकेलना होता है तो उसके लिए कमेटी बना दी जाती है, किसी काम को जल्दी न करना हो तो उसके लिए कमेटी बना दो । कोआपरेटिव सोसाइटियों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि यह एक स्टेट सब्जैक्ट है और इसके बारे में आज तक यह शिकायत रही है—यदि मुझे ठीक तरह से याद है तो हमारे मन्त्री महोदय ने धीरे आवाज में कई दफा कहा है कि जितना सहकार हमें राज्यों से मिलना चाहिये उतना हमें नहीं मिल रहा है । जितना यहां से इस सम्बन्ध में स्टेट्स से लिखापढ़ी करते हैं उतना स्टेट्स नहीं करते हैं । यदि यह बात सच है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कमेटी करेगी क्या ? यह कमेटी कुछ नहीं कर सकती है जब तक स्टेट वाले इस बात के लिए तैयार न हों, इसके लिए उत्साहित न हों । यहां की शिकायत यह है कि वह इस चीज की चाह नहीं रखते जितना सेंटर उन्हें इस काम के लिए पैसा देती है वह उसका ठीक उपयोग नहीं करते । इसलिए मैं नहीं समझता कि इस तरह की कमेटी कायम करने से कोई खास मतलब निकलेगा । मैं यह जरूर मानता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में बहुत कुछ कर सकती है । सेण्ट्रल गवर्नमेंट इतनी मदद दे रही है, इतना पैसा दे रही है तो उसे चाहिये कि वह उन पर अपना सुपरवीजन भी रखे । आज इस मामले में जितना सुपरवीजन और कण्ट्रोल की जरूरत है उतना हम नहीं देख रहे हैं : सरकार जब स्टेट्स को इस काम में जितना पैसा देती है तो उस पर उसका कंट्रोल होना ही चाहिये । आज कोआपरेटिव सोसाइटीज और कोआपरेटिव मूवमेंट के मामले में जितना सेंटर का सुपरवीजन और कण्ट्रोल होना चाहिये उतना नहीं है । जब सरकार इस काम के लिए पैसा देती है तो उसका कण्ट्रोल भी होना चाहिये । मैं यह बात नहीं मानता कि इस कमेटी के कायम होने से कोई काम होने वाला है । मैं यह बात मानता हूं कि हमारे जो मन्त्री हैं उनमें पूरा उत्साह है, उनमें विश्वास है इस कोआपरेटिव मूवमेण्ट में लेकिन उनकी हर वक्त यह शिकायत रहती है कि स्टेट्स वाले मेरी बात नहीं मानते हैं और न सुनते हैं । स्टेट्स वाले जिस तरह उनकी बात सुन सकें, उनकी बात मान सकें, ऐसी कोई तरकीब हमें सोचनी चाहियें इस की तरकीब ही से यह काम कामयाब होने वाला है, कमेटी कायम करने से कोई काम निकलने वाला नहीं है । क्योंकि हम सब लोग समझते हैं कि यह जो सोसाइटी का ढांचा है, अलग अलग सोसाइटीज के जो ढांचे हैं उनमें कुछ कमी है ऐसी बात नहीं है । ये कागज में बहुत अच्छे मॉडल हैं । सोसाइटियों का मौडल बहुत अच्छा है लेकिन कमी है काम करने वालों की और करवाने वालों की । अगर आपको कोआपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ाना है तो आपको उनमें कोआपरेशन की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी । जिस तरह मरे हुए आदमी में प्राण न होने से उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसी तरह अगर हम सब लोग आपस में कोआपरेशन नहीं पैदा करेंगे तो कोआपरेटिव सोसाइटीज प्राणविहीन आगे नहीं बढ़ सकतीं । आज देश की

हालत यह है कि देश में डिसइन्टिग्रेशन बढ़ रहा है । अगर आप देश में इन्टिग्रेशन लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ सहकार यानी कोआपरेशन है और हमें उसको बढ़ाना होगा । हम कोआपरेशन से देश में सब चीज़ ला सकते हैं । परन्तु वह तब ही आ सकती है जब हम में वह भावना हो, एक दूसरे के लिए प्रेम हो, एक दूसरे की मदद करने की चाह हो । आज हमारे दिलों में जो अन्दरूनी बात दिखलाई देती है उससे सोसाइटीज़ का काम आगे बढ़ने वाला नहीं है । इन बातों की ओर, जो असल बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, हम सब को ध्यान देना चाहिये और मैं मान नीय मन्त्री महोदय से भी यही प्रार्थना करूंगा कि वे भी इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दें ।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Mr. Vice-Chairman, Sir, I think the Resolution that has come before us has come at a very opportune time. I would bifurcate the Resolution into two aspects progress of agriculture and progress of co-operatives. I think every Member of this House is aware that we have been failing in agriculture. Even the late Prime Minister had remarked that if we failed on the agricultural front, in the matter of agricultural production, all our Plans will be of no avail. His prophetic words have, I think, come true today. In spite of the large PL 480 imports we have to go in for further imports. What is the reason? The reason is that our agricultural production is not keeping pace with the demand. I believe that is a question that needs to be looked into much more seriously than is being done. There is also another reason. We are shutting our eyes to facts. We have got certain ideas, certain dogmas, before us and we refuse to look beyond them or on either side of them. We are just looking at them. I think that is where we have gone wrong completely.

Now, the experience of co-operatives unfortunately in this country has not been very happy. Mr. Nijalingappa, a very responsible Congressman—I think he is Chief Minister now—has said not very long ago something about this. This appeared in *The Indian Express* under his name:

> "Mr. Nijalingappa expressed his regret and shock that the co-operative movement in the State had left some blank patches behind the much-trumpeted progress . . ."—

Anything that the Congress does is trumpeted and the co-operatives are much trumpeted but there are many many blanks behind. I heartily agree with him—

> "The sight of dust-ridden bandicoot-infested institutions angered him. A number of societies which had been brought to his notice had been working without audited accounts and a General Body Meeting for years on end. Large-scale defalcations in these were not unheard of. The co-operative movement lacked trained people to work as inspectors and supervisors. Many spurious people had made the movement a heven for easy money. All these defects have to be rectified forthwith with a clear mind and with determination."

This was in August, 1962; we are now in August, 1964. How far has this determination taken us. I would like to ask. The experience in the other States is not different. I am quite willing to grant that there are some co-operative societies that have done well but I would like to hear the example of good agricultural co-operative societies. Those examples are lacking at least in our country. About collectivisation, why not listen to what Mr. Khruschev says, about production by collectivisation? He has himself admitted that collectivisation has not yielded increased production. Pro-

3 P.M.

[Shri Dahyabhai V. Patel.]

duction has been falling. That is an admission by the Head of a State which has gone in for large-scale collectivisation.

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated): Where do you get that from and could you give us the question?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Certainly. The following excerpt from an article in the "Financial Express" of March 9, 1962 indicates the change:

> "To increase output, Mr. Khruschev, himself has been suggesting 'material interestedness', to give the peasant a material share if he manages to increase output. The official paper "Kommunist" emphasised that the maximum utilisation of labour resources demands a further increase in collective and individual 'material interestedness' . . ."

SHRI G. RAMACHANDRAN: That does not bear out the meaning you gave earlier.

(Interruptions)

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: If you will be only a little patient, you will get it. Here it is. It is in quotations:—

> "The 'capitalist' principle of profit motives seems to be the best and the most potent fertiliser to revive the 'ineffective socialist pattern' of Soviet agricuture."

SHRI CHANDRA SHEKHAR: But it is the comment of the "Financial Express", it is not Mr. Khruschev's.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: But gal): It is the view of the "Financial Express" and not the views of Mr. Khruschev.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: He may not be quoting in the Russian language, but he is quoting the experience there. And do not we know, after fifty years and sixty years of collectivisation, why they have to import wheat from America occasionally? And why has China to do it again and again?

SHRI G. RAMACHANDRAN: Has he the slightest information that Mr. Khruschev and the Russian Government have given up collective farms?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Thank you. You are supporting my point.

SHRI G. RAMACHANDRAN: I say they have not given up collective farms. That was my question. Have you any information, can you produce one of evidence to show that the Russian Government has given up collective farms? I say, no.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am not saying they have given up collective farms, but they have very radically modified their policy of complete collectivisation. They are allowing private initiative a little more scope than they did, because it is private initiative that is necessary.

SHRI G. RAMACHANDRAN: May I add one sentence before he resumes? When I was in Russia with Mr. U. N. Dhebar, one of the proudest things that Mr. Khruschev spoke about was the collective farms. We were taken around and what we saw was astonishingly good.

SHRI C. D. PANDE: May I speak of the experience among the East European countries? In the East European countries there were collective farms. Along with the collective farms every farmer or peasant has got half an acre of private land. The private land is prospering like anything. It is green and it is a treat to the eyes, whereas the collective farm has dwindled. It has been going barren and it is not well cultivated.

PROF. M. B. LAL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, may I know whether we are discussing cooperation or collectivisation?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I think they are allied subjects.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): It relates to agricultural production.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: They are allied subjects. I think the point that I raised has brought out clarifications from two eminent Members of this House. I think that is enough as far as my point is concerned.

Let me go one step further. I will quote Mr. S. K. Dey. The Union Minister of Community Development and Cooperation is reported to have disclosed on August 17, 1964 that out of 1,20,000 primary co-operative societies registered in the country about 60,000 do not possess even a board. They exist only in the Government's register. Mr. Dey is also reported to have stated that the small co-operatives had defeated all attempts by the Government to have them amalgamated into viable units, so that they could function effectively. This is the state of agriculture and co-operation in our country. I am speaking with a little experience myself. Sitting in Bombay I have a number of friends in Maharashtra and at the suggestion of some friends I registered a co-operative society in Maharashtra to utilise a lot of hilly, waste land, to grow mangoes. Well, the society is working. The mango is a slow-growing crop. It grows and it is producing. The Director of Agriculture of the State of Maharashtra was very pleased. He commented very favourably on it. I applied to the Department of Horticulture. I know that the State was giving long-term loans for horticulture. No answer. First it was said that the Bombay Government did not take advantage of it as it was only available for C.P., Dr. Punjabrao Deshmukh's State. When C. P. was merged into Bombay I pointed out to them: "Now, this is one State. There cannot be two laws for the same place." Well, I have been knocking my head from pillar to post, from Minister to Minister, saw the Secretary of the Agriculture Department and the Secretary of the Co-operative Department, primarily because my friends there have asked me. Otherwise, I have no need to approach them, because they will only patronise their supporters. I have not been able to do anything. I have been telling these friends there that the society has produced a good crop. They export it. But the Government will not look at us. I am not one who can work behind Mr. Manubhai Shah to gain an incentive bonus. I am not one who can curry favour with the Government of Maharashtra so that they would look at me. They will only look at the grapes in Nasik to which I was referring. If friends want to know more about it, they might better go and ask Mr. Deokinandan Narayan.

SHRI A. B. VAJPAYEE (Uttar Pradesh): Are they not sweet?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: They are more sweet. Even though land ceiling has been applied, the Chief Minister of Maharashtra has got a 50-acre farm where he produces grapes. He switched on from sugarcane to grapes. And the fifty acres that he has got is one of the family. Many others have got fifty acres. You can put two and two together. This is how land ceiling is applied.

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra): Sir, the information being given by Mr. Patel is absolutely false and wrong. I know the Chief Minister's land. I have also gone to his place. In the first place, he had cultivated about two acres and now he has tried to get twenty acres of land under grapes. I know it. I have seen it with my eyes. It is not a fifty-acre land. The land belongs to the whole family and not each member separately.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I will stand corrected. From two it has gone to twenty. From sugarcane it has gone to grapes. That is what I have said.

SHRI M. M. DHARIA: That is also not correct. It is not from sugarcane that he has gone to grapes. On the contrary, the hon. Chief Minister had dug wells and it is out of that water that he has now, for the first time, been trying to evolve horticulture on lands which were not even cultivable.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: My friend is mistaken. I am saying that he has done well because grape produces a much better yield per acre than sugarcane.

SHRI C. D. PANDE: What is the harm?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: That is what we want our farmers to do. I am saying that the farmers must be told, advised to produce, what produces better results, and that is where our Department of Agriculture comes in.

SHRI C. D. PANDE: You can produce wine out of grapes.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: If the crop produced gives a better return, why do not you advise our agriculturists to do it?

(Interruption)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Dr. Pande, let him continue please.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: What I was trying to tell you is that our Government has been shutting its eyes to facts. Very recently I may tell you when we were in this dire food situation and the new Minister of Food and Agriculture took over with so much enthusiasm, I understand the Consul for Israel went to him and explained to him: "This is how we have made a success of agriculture in Israel." In Israel they have tried land ceiling, they have tried co-operative societies. They offered to send their men here free if we wanted. Actually their expert has passed through India on his way to Nepal in order to see and advise the Government of Nepal. There are a few simple things that help us to produce more. For instance, they saw the agriculture in Rajasthan, and one of the defects they pointed out was that the plough that is used is like a nail. It furrows into the land, but because of the strong winds of Rajasthan, the best soil for the plant, the thin soil is blown away by the winds. By applying a little piece of metal or wood behind that nail, it presses that valuable material back into the land, and that will increase production. Better utilisation of water in places where we are short of water would produce more. The Consul for Israel is waiting for an answer for nearly two months after his offer. I understand the External Affairs Ministry is scratching its head as to whether we can give clearance to this project, which means two or three people coming only. He does not want your money even. Besides, we have the example of one Mr. Halevi—I think you have seen the Israel magazine, how he came to Sevagram to help the people to produce more without any extra cost. We are not prepared to learn from people because they belong to a different caste, if I may put it that way. The same is the case with Taiwan. In Taiwan they introduced land ceiling. They gave land to the tiller and their agriculture has increased in the last two years to 300 per cent. Mr. Vice-Chairman, I tried to bring some literature with me from there. I was told that it was banned. I told the Customs officer: "You can take steps against me. I am taking this book with me." I have just got a letter from Raja Mahendra Pratap. He said that he tried to do something years ago in 1961. He was told that no literature would be allowed. He tried to import a lot of literature particularly which helps agriculture. It showed how they made a success of agriculture by introducing land ceiling and giving land to the tiller, how they increased their production of rice by 300 per cent., and so on. That was

not allowed because somebody in the Finance Ministry, I am told, gave an order in 1961. I am surprised that this Government did not revise their order even after the Chinese aggression. The Chinese, the Communist Chinese I mean, can dump tons of literature into India, anti-Indian propaganda. There is no ban on that even after the aggression. But literature that is likely to be useful to us in this country, to help our agriculture, is banned even till today. Sir, I have on my return from Taiwan explained both to the Minister of Foreign Affairs and to the Minister of Food, Mr. Subramaniam that the Government of Taiwan is willing to help us officially or unofficially. (*Interruption.*) They say that they are willing to send men officially or unofficially. But we are not willing. Is the only centre of learning Moscow? Are there no other people in the world? What I want to say is that the approach of our Government to the problem is wrong. Whether it is Mr. Dey or Mr. Nijalingappa, they all admit that they have been a failure. Why don't they look at facts straight in the face, cure the disease or cut out or amputate that part of the body which has gone rotten and start afresh on a clean slate?

SHRI M. M. DHARIA: Mr. Vice-Chairman, our country has been facing several crises and particularly the crisis of food that we are facing today. If that crisis is to be solved, I think, Sir, that a greater need has arisen in this country to build up our co-operative movement and the community development programme.

I was patiently listening to the opposition leader, Mr. Dahyabhai Patel, and his remarks so far as the agricultural co-operatives are concerned. I think unfortunately Mr. Dahyabhai Patel has taken agricultural co-operative as only co-operative farming societies. That will not be proper. According to me and even according to the Government, if I mistake not, under co-operative agriculture, co-operative farming, co-operative credit societies, co-operative marketing, co-operative processing industries, co-operative godowns, co-operative cold storage, animal husbandry on co-operative basis, service societies on co-operative basis, lift irrigation project on co-operative basis, building of percolation tanks and such other things necessary for the farmer on co-operative basis, all these could be construed as co-operative agriculture. Having regard to all these activities that are spread all over this country, we should feel proud that within the last few years we have definitely progressed much and at least we have laid the foundation in this country whereby we can think of better progress. Particularly in these critical days, had those co-operative societies not been brought to the village level, I think by this time it would have been absolutely impossible to face the hoarders and blackmarketers that exist in the country. Of course they are bound to say that this co-operative movement should not grow because if it grows, naturally they will have to wind up their business. The major difficulty that this movement is facing today, the major opposition, is from those who are opposed to this co-operative movement, who are opposed to socialism, and who are opposed to democracy as well. When I look at the co-operative movement, this co-operative movement is not only going to bring socialism in this country but at the same time it is going to deepen the roots of our democracy. If we look at the movement, there are several aspects, Sir. The hon. Minister concerned has also shown his approach towards this movement and he has stated in categorical terms that the time has come when we shall have to survey the whole movement. But that does not mean that he is opposed to the movement. What I mean is in case we want to encourage this movement, in case we want that this movement should stand on a good basis and sound foundation, definitely we shall have to survey what we have done in

[Shri M. M. Dharia]

the past and what we shall do in the future. Having regard to all these activities I feel that today is the most opportune time when we should examine what has happened in the past and what we should pledge for the future.

So far as agriculture is concerned, I need not say that we are lagging far behind in our average production. It is in every field and it is not only in agriculture. In case we think of wheat or rice we know that per hectare the production of wheat in the U.S.A. is 1500 kg.; in Canada it is 1375 kg.; in Australia 1250 kg.; in Asia it is 750 to 1000 kg.; in India we are a little less than what it is in Asia. Similarly if we look at the rice production, in Australia they produce 6400 kg. per hectare; in Japan they produce 5000 kg.; in Burma they produce 1700 kg.; and in India we have not been able to produce even 1400 kg. per hectare. Particularly if we look at Japan and Australia, we shall find that within the last fifteen years they have taken their average up to a much high figure. In Australia it was 4400 kg. in 1950 while in 1960 they have gone up to 6400 kg. In Japan it was 3400 kg. in 1950. Within a span of ten years they have gone up to 5000 kg. So far as India is concerned it is true that we have been making some progress. From 95 per cent. we have come to 139 per cent. so far as agricultural production is concerned, which is not satisfactory.

So far as the milk yield is concerned we find that in the Netherlands per cow the yield during the lactation period is 4150 kg.; while in India it is only 220 kg. There are figures for various other countries but I do not intend to take up the time of the House so far as other figures are concerned. But when we look at the Netherlands or Denmark or Belgium or Izrael, I think we are far behind. In Izrael a cow gives 4,330 kilograms of milk in one lactation period while in India it is only 220 kilograms in the lactation period. You see how far we are behind. And how are you going to build up all these activities? That is the problem, and I think it is not the poor farmer who is in a position to do it. It is only through the co-operative movement that we can definitely build up all these activities, and it is from these perspectives that we have to look at the co-operative movement. Many people say that the co-operative movement has become a failure in our country. I am not of that opinion, I am of the opinion that several people did come forward to enter that movement. Those who worked hard, those who served the co-operative movement as a missionary work, with a missionary zeal, have been successful in the movement and those who have joined it as a fashion have failed. It is a fact. And whereever we have worked hard, we can see that there are good results, particularly in Maharashtra. I belong to Maharashtra, and being one of the office-bearers of the Pradesh Congress Committee, I have had the opportunity of visiting several districts in my State. I have gone from district to district and I can say with pride that this co-operative movement has changed the face of that particular area of our country. Particularly in Sangli District or in Ahmadnagar District or in Poona District, if we walk into the rural area, we can find that practically the picture has been changed. There we find that the farmers have come together and for being members of the co-operative society, they are even mortgaging their property, particularly for being member of the lift irrigation society. They have divided the Sangli District into 28 parts and for every part they are having a dairy, they have poultry farming, they are having their piggery societies, they are having their service co-operatives, they are having their industrial co-operatives. These things are fetching the poor farmers who had previously no good income, a nice income and I have no doubt in my mind that in the years to come the whole of that dis-

trict will become an agro-industrial district and we shall be having successful agro-industrial societies there. So far as the Sangli District is concerned, because of the co-operative movement, particularly the agricultural co-operative movement, within the five years to come we shall find about 50,000 farmers having some sort of additional business, 50,000 farmers will be working in other fields and producing more. It is only in that way, if we plan and develop the society on a sound foundation, that we can change the whole picture of our country, and that is the need of the day.

Sir, so far as the Indian economy is concerned, we can have a look at those figures as well, and what do we find? The agricultural side which is producing to the tune of Rs. 6,000 crores of our national income, what have we spent on it? We have been giving crores of rupees to other industries in the private sector and for other sectors. What about agriculture? What about the poor agriculturists? What help have you been giving them? Merely giving a help of Rs. 1,000 crores during the whole of the Plan is nothing. I think, Sir, the time has come when we shall have to give more and more to these farmers, particularly to those who are not getting any water for irrigation. Most of the land is such that there is no source of water and naturally such farmers need more help from the Government and from the State. If that help is given, I have no doubt whatsoever in my mind that the whole picture of our country would be changed.

Therefore, my submission would be: in order to face the present crisis, let us think in some other terms. The whole bias of our economy should be towards agriculture; it should be an agrarian bias, and that alone would solve the problems of this country. Most of the villages of this country—five lakh villages—are such as are absolutely underdeveloped. A lot of development has to be undertaken, and if this development is to take place, it is the co-operative movement which alone can be in a position to develop that area and not otherwise. The farmers in those rural areas are a needy people and their needs should be satisfied, and it can be done only through co-operative societies; no individual can do it.

About the co-operative collective movement it was said that it has lost everything during the last ten or twelve years. I do not agree with that view. Even in Russia we find that it is through collective movement that they have come forward. Whether that movement is democratically good or bad may be a point of dispute but there is no doubt whatsoever that it is because of the collective efforts of people that a country like Russia was able to rise to such a high stature, and this is one of the two blocs, it is one of the major countries which is now shaping the destiny of the world.

SHRI S. S. MARISWAMY (Madras): Do you refer to their rocket flying as an achievement?

SHRI M. M. DHARIA: I may submit that I am a believer in democracy and socialism, and if we want to avoid . . .

SHRI S. S. MARISWAMY: I do not question your faith in socialism. You said that Russia has done so many things. "Are you referring to their rocket flying?" I asked.

SHRI M. M. DHARIA: My submission is that if we want to avoid that sort of dictatorship, then naturally we cannot accept their methods. There are not many co-operative farming societies here. If that question comes up, the answer is also simple. Here we are not having any sort of dictatorial methods. It is left to the good will of the farmers. They should come together and form their co-operative societies and they should work through co-operative societies, produce through co-operative societies.

[Shri M. M. Dharia]

That has been our submission, and we have been trying to persuade them to take to co-operative farming. So far as the agricultural co-operatives are concerned, definitely thousands and lakhs of farmers have come together and they have strived hard for the fulfilment of our aims and ideals, and for that job, what is necessary is altogether a different approach. Today this bureaucracy is coming in our way, today the vision of particular people who have not yet accepted this idea of socialism, who have not yet accepted this idea of co-operative movement, is also coming in our way, and that approach shall have to be changed. As was rightly referred to just now, what is our policy of imports, what is our policy of exports? If we take the illustration of groundnuts, the poor farmer is not getting even Rs. 50 per bag of groundnuts and the man who has got the quota or permit to export it is getting to the tune of Rs. 120 per bag. Why is this difference and why should such an amount go to that big quota-holders and not to the poor farmers? If it is done through the co-operative society right from the production stage to the marketing stage, I have no doubt in my mind that this co-operative movement will definitely succeed and from that angle, my submission would be, we should look at this problem. It should altogether be a different approach. We should have godowns formed on a co-operative basis. We should have cold storages, we should have animal husbandry, we should have poultry farming, we should have piggery farming, we should have fisheries on a co-operative basis; we should have service co-operatives. Through service co-operatives we can do several things. Supply of seeds, fertilisers, manures, insecticides, pesticides, implements, iron sheets for their huts and for pipes, transport, medical aid for animal husbandry, training of farmers, bunding and ploughing, all these things are possible through service co-operatives. For these things a lot of capital is necessary. Are we prepared to invest that capital? Sir, the time has come when we shall have to change the present atmosphere. In America in agriculture 60 per cent. of the income is not through crops, 60 per cent. of the income is through poultry farming, piggery and other forms of animal husbandry which the farmer does. And here in India we do not have even five or six per cent. of income from these other sources. It is not proper. The time has come when we should see that we also reach that aim. If we do that, we can raise the standard of living in this country, we can raise the standard of the poor farmer. And it is only through the co-operative movement that we can do it. Therefore, I believe that the challenge has to be accepted. It is the challenge of our destiny and it must be accepted. It can be accepted only through the co-operative movement and not otherwise. Even for the establishment of democracy and socialism, it is this co-operative movement which alone will come to our help and no other movement can foster that. It should be developed day by day. We should see that the private sector no more dominates the poor farmer. Through co-operative movement alone the farmers in the country will benefit.

Thank you.

PROF. M. B. LAL: Sir, some sixty years ago the first Co-operative Act was passed. But, as we know, for long the scope of the co-operative movement remained very limited and its impact on the national economy was more or less negligible. It hardly penetrated into the agricultural economy in the pre-independence days. After independence its importance was no doubt duly recognised. Almost all political parties and almost all political thinkers and economists duly laid stress on the importance of the co-operative movement, and undoubtedly in last fifteen years or so some progress has been recorded. Yet the progress is even today insignificant. Its impact on our agricultural economy is still very limited. Agriculturists continue to be largely under

the grip of moneylenders and foodgrain traders.

Sir, it is said in annual reports that while in the pre-Plan period, co-operatives extended only 3 per cent. of credit facilities required by agriculturists, at present about 10 per cent. of credit facilities are being provided to agriculturists by cooperatives. But all the same from these very records it is obvious that their impact on our agrarian economy has been very insignificant. As has been pointed out by a distinguished Member of this House, the poorer sections are the least benefited by our co-operative movement. Whatever credit facilities are extended, they are utilised mostly by big peasants.

Sir, some marketing societies have also been established. Yet these marketing societies are handling only an Insignificant portion of the trade in foodgrains. Most of the co operatives, as we know, are not functioning the way they should function. No less a person than the Minister-in-charge of Co-operatives has recognised that the co-operatives are not functioning in a proper manner and that the cooperatives have not taken sufficient deep roots in the country. I do endorse the appointment of a committee composed of Members of Parliament to look into these matters and to suggest ways and means of promoting co-operation in the sphere of agricultural economy.

Sir, I need not point out to this House that agriculture is the mainstay of the Indian economy. Seventy per cent. of the Indian people are living on agriculture and others also largely depend for their very existence on agricultural products. In recent years agriculture has not made sufficient progress. We are yet far off from being self-sufficient in food and we are faced today with a considerable shortage in agricultural products. It is our duty to duly recognise this fact and to understand that for our economic development agricultural development demands the highest priority. It deserves our greatest attention and consideration.

Sir, we Socialists are proud that in promoting co-operation all over the world Socialists have played a very significant role. Socialists also recognise co-operation to be an important foundation of socialist economy. But all the same co-operation cannot be said to be the monopoly of Socialists. There have been many economists and social workers who were not socialists but who worked for the cause of co-operation. If co-operation is an important foundation of socialist economy, the infra-structure of co-operation is badly even for the building up of our agricultural economy based on small peasant proprietorship. Sir, I am definitely of opinion that co-operation should not be treated as an ideological issue, should not be treated as a party issue, but it should be recognised as very important for the development of our agricultural economy on which depends the prosperity and the happiness of the people of India.

Sir, I wish here to point out that co-operation and collectivisation are not to be confused. Almost all over the world there are democratic socialists who are definitely opposed to collectivisation and feel that collectivisation has not contributed as much to agricultural development as it has caused hardship to hundreds of thousands of small peasants. But they distinguish between collectivisation and co-operation and they feel that co-operation should be promoted. Those who try to confuse co-operation with collectivisation either try to popularise collectivisation or try to deprive the people of India of the benefits that are likely to accrue to them from co-operation. I hope that even member of the Swatantra Party who are obviously opposed to socialism would duly recognise the importance of the co-operative movement and instead of confusing co-operation with collectivisation, will try to keep in their minds the distinction between the two and will

[Prof. M. B. Lal]

work for the growth of co-operation on right lines so that our agrarian economy may have a sound foundation, a sound and healthy infra-structure.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Even after the Seventeenth Amendment?

PROF. M. B. LAL: I do feel, even after the Seventeenth Amendment co-operative is necessary. Even if you pass the Eighteenth and the Nineteenth Amendments to the Constitution modifying the right to property considerably, even then, co-operation will be needed. This is a fact which is to be recognised by members and the leaders of the Swatantra Party.

I wish to invite the attention of the House to one important fact. In the thirties of this century the world was faced with economic depression and economic crisis. The agrarian economy of Norway and Sweden was also faced with considerable economic crisis and it was co-operation that saved Norway and Sweden during the days of economic depression. On the basis of co-operation they built up their dairy industry which is flourishing very well in these two countries. So I wish to point out that while co-operation is an important foundation of a socialist economy, if also provides a necessary infra-structure for agrarian economy based on small peasant proprietors. Therefore, let this co-operation be above party politics. Whether we agree with socialism or not, all of us should see that co-operation flourishes in this country. I wish the Parliament to agree to the appointment of a Committee and I wish the Committee to come forward with some constructive suggestions which might enable us to provide small peasants of India the infra-structure of co-operation.

With these words, I support this Resolution.

DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA (West Bengal): Sir, friends have spoken enough on the need for the co-operative movement. I stand not only to support that the co-operative movement is one of the bases of the solution of our present-day economy of our country but I also stand to say that we need today a more active and strong co-operative movement in our country—I mean co-operative movement of all sorts. I would like to point out that the movement should be taken more seriously both by the people and by the Government. There can be a good plan, and there can be very good planning of the co-operative movement but merely the plan will not help us but real execution of that plan will be needed. In this connection I would request the Department through you that the Department should be more active, more alert and more helpful. The Co-operative societies need the help and advice from the different experts and their advice and help should be given in time. I say that it should be given in time. We often see that the advice and help do come but when the time is up. That is why I like to point out that.

I would like to draw your attention regarding registration of co-operatives. Sometimes it takes a very long time particularly in small towns and villages. I also would like to draw the attention to the supply of loans in time, supplying particularly seeds and good seeds in time. I repeat 'in time' again. To establish a democratic socialist India we must form more and more active co-operative societies and for that we need the time and help of all sorts from the experts and all concerned in good time and not when the time is up. Thank you.

SHRI G. RAMACHANDRAN: Sir, it is a pity that even such a life-giving programme as co-operation should be made a kind of a shuttle-cock between political parties and it is equally a pity that we confuse all forms of co-operative efforts, one with the other. Now in this Resolution you have this reference, to co-operative agriculture. Now this is a very compendious term, if I may say so, and as I thought about it, agricultural co-operation would in-

clude credit-cum-service co-operatives, co-operative marketing, co-operative processing and co-operative joint-forming, etc. as the many items. I remember some time ago a great deal of controversy centred round co-operative joint farming. I remember a high-level seminar which considered this subject and I also remember how it was emphasised again and again that in a co-operative joint farming society members do not give up the ownership of their bits of lands. That happens in collectivisation. There is now confusion between co-operative joint farming and collective farming and as soon as you come to the word 'collective' farming, it is like the red rag before a bull and the bull begins to charge at this red rag. Then in order to support ones own assumption, you begin misquoting from what happens in other countries. What we are really dealing with to-day is agricultural co-operation under different headings. In regard to co-operative joint farming I have some experience of some societies and I myself am not certain that they have done very well. My friend who spoke a little earlier spoke about something which is of very great importance in the consideration of the whole question. He said in America for instance, if you look at agriculture, agriculture includes nearly 60 per cent. of other subsidiary activities like the poultry and the dairy etc. and other items of work which centre round the farm. This is even more necessary and important in India. Then it was said that in India if you look at the picture you have only about 5 to 6 per cent. of the subsidiaries gathering round agriculture. I think in India even more than in America and the advanced countries, agriculture must be put into the setting of innumerable other activities. For instance, the Minister for Agriculture is now saying: 'Don't concentrate merely on the growing of corn and grain. We must have fisheries. We must have poultry. We must have kitchen gardens, and many other things like that." Now, many years ago, Mahatma Gandhi said the same thing. I remember Mahatma Gandhi saying that agriculture by itself will not be enough for advancing the prosperity of a people. Unless agriculture is linked intimately, day to day, with innumerable other agro-industrial activities, by itself, it ceases, in the long run, to produce a prosperous State. So agriculture and agro-industries, joining hands together, even in the agricultural co-operative movement, might give us better results, and this is the whole case for the programme of cottage, village and small scale industries.

I suggest once more, Sir, that we must release our minds from the idea that we must look upon agriculture from some party point of view.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

I have good friends in the Swatantra Party; the leader and the founder of the Swatantra Party is one with whom I have worked, intimately for many years and I do not think Shri Rajagopalachari will throw a single stone at service co-operatives, co-operative marketing, co-operative processing, etc. So let us look upon the subject as something by itself, as something good and necessary every party, for every group, for the agriculturists and the industrialists, for all those engaged in productive work. And if you look at it that way then I think a great deal of the inhibitions we suffer from will no longer worry us.

Then finally, Madam, anyone who, in the year 1964, imagines that we can build up successful agriculture in India on the basis of the individual farmer, is living in a fool's paradise. The idea of the individual farmer taking care of agricultural production as an individual owner and producer is completely outmoded. Looking at it from innumerable points of view it can be proved that what has become necessary today is to pool resources. The methods of pooling might differ from State to State and from industry to

[Shri G. Ramachandran]

industry, but the necessity for pooling resources together is the first basic need to increasing production in the agricultural field as well as in that of village industries and cottage industries. Now, if this is accepted, then all of us must sit together to plan co-operation in such a way that it can bring back life to the villages which are slowly perishing in spite of many of the things that we are doing. I live in a wholly agricultural, and rural area. I have seen some of the changes that have taken place in the last fifteen to twenty years. There are changes no doubt, but on the whole if you look at the picture, the changes are not commensurate with the growing needs of the people today. So let us not make co-operation a shuttlecock among political parties. Let us accept this life-giving method of production and let us take the people with us step by step and develop the co-operative movement. Just as agriculture without the setting of agro-industries in the rural areas cannot stand the test by itself, equally it is important to carry with us the mind of the people in regard to agricultural co-operation. Now how are we to do that in this country where illiteracy is so rampant, where the elements of adult education have not yet reached the masses of the people?

I come back therefore to the idea if we can build up the life of the farmer and his family, then you do the biggest thing you can for agriculture. Agriculture is an occupation which human beings have to undertake and if you do not take care of the farmer and his family and that is the business of the Ministry of Community Development, it is their work—if at that point we are weak, then nothing else that we do will succeed in increasing production.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. M. C. Shah. Not here. Mr. Patra.

SHRI N. PATRA (Orissa): Madam Deputy Chairman, co-operative agricultural farming is not a new concept. It is an age-old practice, but under Western influence it had wanted and under foreign domination individualistic attitudes grew in us and the co-operative attitude declined. Formerly the farmers were helping each other at the time of harvest, and at other times, in weeding out operations etc. But that good practice we had gradually forgotten. In my opinion co-operative agricultural farming is the only panacea to uplift the poor agriculturists. Seventy-five per cent of the poor farmers, the agriculturists, possess about 5 acres and less of the cultivable land, and with half an acre of land or so possessed by poor agriculturists there is no scope for him to maintain himself and his family meeting the expenses of other necessities of life. Co-operative agricultural farming is the only panacea to cure gradually all the maladies which the poor agriculturists are confronted with. We have to help the poor agriculturists and the landless labourers, who idle away their time without any paying work to do for the major part of the year. You have to inculcate in them the idea of co-operative farming and utilise the man-power which is now practically going waste. During the seventeen years of our independence, though we have tried to ameliorate the condition of the down-trodden through the process of industrialisation of our country; we are still at the fringe of solving their problems. Therefore co-operative farming is the only process through which we can solve most of their problems. Co-operative agricultural farming should go hand in hand with the setting up of ancillary industries. Production of foodgrains is no doubt the most essential thing but, along with that, to help the agriculturists you must try and set up ancillary industries and utilise their time now lying idle without any productive work to do. Along with piggery, poultry and dairy, farming, and production of honey and cattle-breeding, we have to help the agriculturists with necessary finance,

and unless you conform to the technological processes, and unless you try to apply the advanced scientific methods to agriculture, it is impossible to raise the production which you need now. Now we are depending for our maintenance, for our food requirements, on foreign countries, which is most undesirable. So the utmost attention and the foremost priority has to 4 P.M. be given to the sector of agriculture through the formation of corporative and collective farms. Unless you do that, you cannot solve the problem of these poor agriculturists possessing small holdings. Unless you get these poor agriculturists together they cannot stand on their own legs. They cannot maintain themselves on a tiny plot of land. As I said previously about 75 per cent of the kisans possess below 5 acres of land. To enable them to pool together their tiny bits of land into proper sizes, into sizeable acreage, and viable units, we have to encourage these agriculturists to get together in cooperative farms to ameliorate their conditions and for better utilisation of their land. Therefore, I support and recommend this Resolution about cooperative farming which my hon. friend Shri Sri Rama Reddy has put forward before the House.

श्री चन्द्र शेखर : महोदया, मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन हमारे माननीय दो सदस्यों ने जो भाषण दए---प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल और श्री जी० रामचन्द्रन् ने, उसके बाद मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूं ।

आज देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी वास्तविक समस्याएं राष्ट्र के सामने हैं उनका समाधान करने के लिये हम लोग स्पष्ट रूप में सामने नहीं आते । मैं ऐसा समझता हूं कि सहकारी आन्दोलन और खास तौर से कृषि क्षेत्र में जिसकी आज चर्चा की जा रही है, वह मौलिक रूप से एक राजनैतिक आन्दोलन है । अगर स्वतन्त्र पार्टी के लोग उसका विरोध करते है तो अचेतन रूप में उसका विरोध नहीं करते उसको सोच समझ कर उसका विरोध करते हैं । गांधी विचारक होने के नाते श्री जी० रामचन्द्रन् यह जरूर समझते होंगे कि इसको राजनीति का शटलकाक न बनाया जाय, इसे राजनैतिक परिधि के अन्दर न लाया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में सहकारिता को लाया जाय तो इसमें सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्धों में मूलभूत परिवर्तन होता है । कृषि के क्षेत्र में पिछले हजारों वर्षों से क्या होता रहा है । एक तरफ ६० फीसदी से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ के फार्म हैं । एक एकड़ से कम जमीन वालो के हक में सहकारिता आन्दोलन उत्पादन को बढ़ाने वाला है । जो छोटा किसान है, जो गरीब लोग हैं, जिनकी आकांक्षाएं वर्षों से दबी हुई हैं, जिनका विकास रुका हुआ है, उनको बढ़ाने के लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि विज्ञान द्वारा जो साधन उपलब्ध हुए हैं उनको कृषि के क्षेत्र में लगाने के लिये वे सहकारिता आन्दोलन का आश्रय लें । यदि वे सहकारिता आन्दोलन का आश्रय लेते हैं और यह आन्दोलन सफल होता है तो फिर नतीजा यह होगा कि बड़े लोग जिनका एकाधिकार आज बना हुआ है उनके अधिकारों पर कुठाराघात होगा । माननीय डाह्याभाई पटेल और उनकी पार्टी एक निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती है । उनका व्यक्तिगत विचार अच्छा हो सकता है, उनकी भावनाएं अच्छी हो सकती हैं लेकिन क्या वजह है, जैसा माननीय रामचन्द्रन् जी ने कहा, कि सहकारी आन्दोलन का दूसरे क्षेत्रों में उतना विरोध नहीं किया जाता, जितना विरोध कृषि के क्षेत्र में किया जाता है । बड़ी और छोटी जो के मालिक के अन्दर यह भावना पैदा कर

[श्री चन्द्रशेखर]

की कोशिश होती है---मैं नहीं जानता जनसंघ के भाई यहां हैं कि नहीं---ये स्वतन्त्र पार्टी के भाई, जनसंघ पार्टी के भाई सारे देश में यह भावना फैला रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र मे सहकारिता हुई तो किसानों का स्वामित्व उसके हाथों से चला जायगा । स्वामित्व का झगड़ा किन के लिये है ? स्वामित्व का झगड़ा इस देश में कृषि के क्षेत्र में केवल दो फी सदी लोगों के लिये है जिनका प्रतिनिधित्व डाह्याभाई पटेल करते हैं, उनकी पार्टी करती है, जनसंघ के लोग करते हैं । मुझे अफसोस है कि कांग्रेस केदोस्त इस मौलिक सैद्धान्तिक सवाल पर सही मानी में अमल करने की बजाय खुद बगलें झांकते हैं । मुझे आश्चर्य तब हुआ जब प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी जो जनतांत्रिक समाजवादी आन्दोलन के नेता हैं और समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने यह कहा कि इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है । राजनीति से मतलब किस चीज का है किस चीज का नहीं है यह अन्दाज़ लगाना बड़ा मुश्किल है लेकिन एक बात मैं आपके जरिये बताना चाहता हूं कि जहां भी स्थिर स्वार्थों के खिलाफ कोई कदम अगर देर में भी असर डालने वाला होगा तो उसके खिलाफ स्थिर स्वार्थ के लोग उठ खड़े होते हैं । लेकिन उस आन्दोलन को चलाने के लिये जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके कदम डगमगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस हुकूमत से मुझे कोई बुनियादी ऐतराज तो इस से ऐतराज है कि कांग्रेस के इन सैद्धान्तिक सवालों को गरीब जनता के पास क्यों नहीं रखते ? आखिर सहकार चाहिये, सब लोगों का सहयोग चाहिये, तो किस का सहयोग चाहिये? अगर कृषि के क्षेत्र में, सहकारी आन्दोलन को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आपको कभी स्वतन्त्र पार्टी का सहयोग नहीं मिल सकता, आपको कभी सहयोग जनसंघ का नहीं मिल सकता । यह सहयोग का झूठा नारा, यह सहयोग के बारे में मिथ्याचार जितनी जल्द इस देश में बन्द हो उतनी ही जल्द इसमे कामयाबी होगी ।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नारे का असर क्या होता है ? जैसा रामचन्द्र जी ने कहा, गांधीवादी विचारक लोग यह कहते हैं कि राजनीति को जितनी दूर रखा जाय उतना ही अच्छा है लेकिन बदकिस्मती यह है कि एक समाजवादी होने के नाते मैं यह मानता हूं कि राजनीति का प्रभाव, उस का असर, इन्सान के जीवन के हर पहलू पर होता है और खास तौर पर जहां हम आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जहां हम गरीबों की माली हालत दुरुस्त करना चाहते हैं, वहां पर राजनीति अपने सब से कुत्सित रूप में आती है । एक तरफ स्थिर स्वार्थ के लोग हैं, दूसरे वे हैं जिन के सामने नये समाज के निर्माण का सपना है, जो नए समाज की रचना करना चाहते हैं । यदि यह राजनैतिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है तो फिर सहकारी आंदोलन की स्थिति क्या होगी --वही स्थिति जो आज माननीय डे साहब के नेतृत्व में हो रही है । माननीय डे साहब बयान देते हैं कि सहकारी आंदोलन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो कांग्रस के भाई मान लेते हैं । अभी डाह्याभाई पटेल उद्धरण दे रहे थे कांग्रेस के बड़े नेताओं के । लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या कभी सोचा है यह बात क्यों होती है ? कृषि के क्षेत्र में सहाकारी आन्दोलन सफल इस लिये नहीं होता है कि जो गरीब हैं, जो गांवों के अन्दर रहने वाला है उस के पास बुद्धि नहीं है, अपना हित समझने की शक्ति नहीं है । जिन के पास यह समझने की शक्ति है वे अपने हित को समझ कर, अपनी भलाई को समझ करके अपने इन्टरेस्ट को समझ कर उस गरीब के पास जाते है और कहते हैं सब कुछ करो किन्तु कृषि के क्षत्र में, सहकारिता को मत आने दो । आज डाह्याभाई पटेल उसी स्वार्थ का, उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व इस संसद् के अन्दर करते हैं । आज उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए जब वे चुनौती देते है तो हमारी तरफ से जो लोग समाजवादी

समाज बनाना चाहते हैं, जो सहकारिता आन्दोलन को चलाना चाहते है और रामचन्द्रन् जी ऐसे लोग जो गांधीवादी परम्परा में पले हुए हैं, वे मानव की सद्वृत्तियों की चर्चा करते हैं। लेकिन समाज का निर्माण होता है निश्चित वर्गों के संबंधों के आधार पर। आज हमारे देश में दो वर्ग हैं, एक शोषित वर्ग है, दूसरा शोषक वर्ग। शोषित और शोषक वर्ग का कोई सहयोग ऐसे मामलों मे नही हो सकता जहां पर प्रापर्टी रिलेशन बदलने वाले हैं, जहां पर संपत्ति के संबंध बदलने वाले हैं। महोदया, मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी और शासन इस बुनियादी बात को समझने के लिये नही तैयार है तब तक यह सहकारिता आन्दोलन कभी राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं हो सकता। जिस तरह से एक जमाने में लोगों को समझाने की जरूरत थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अगर सबसे बड़ा अहित किसी का करता है, तो गांवों में बसने वाले किसान का करता है। महात्मा गांधी ने जैसे हमें एक मंत्र दिया, उसी तरह से अगर कृषि के क्षेत्र मे सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्रापर्टी रिलेशन के बारे में, सम्पत्ति अधिकार के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिये। हमको यह कहना होगा कि सम्पत्ति का स्वामित्व जो ऊंचे वर्गों के दो फीसदी लोगों के हाथों मे रहा है उस को छीन कर ९८ फी सदी, ९० फीसदी लोगों के हाथों में देना है और इसमें कुछ संघर्ष होगा, थोड़ा विद्वेष होगा और उसको बर्दाश्त करने की, होनी सहन करने की हिम्मत चाहिये। डाह्याभाई पटेल सामूहिक खेती का जो विरोध करते हैं, वह क्यो करते है ?

SHRI DHAYABHAI V. PATEL: Madam, he has thoroughly misunderstood me. I am not against co-operatives but I am against the collectives.

SHRI CHANDRA SEKHAR: This is what he is saying that he is against collective farming. But he is also against co-operatives. This is my assertion that the Swatantra and the Jan Sangh Parties can never be in support of the agricultural co-operatives because it is against their very philosophy. The Swatantra Party and the Jan Sangh Party are the representatives of vested interests. This agricultural cooperative movement is surely going to strike at the roots of the vested interests in the agricultural sector of our country. So, very deliberately and very consciously the Swatantra Party and the Jan Sangh are opposing this co-operative movement in the agricultural field and it is a pity that the Congress people are not ready to face this political question squarely. They are not giving a clear, bold and determined call to the down-trodden people in the rural areas.

माफ कीजिये, मैंने अपने पुराने दोस्त श्री गोडे मुराहरि जी से वादा किया था कि मैं हिन्दी में बोलूंगा। तो मैं यह कह रहा था कि इस आन्दोलन को . . .

श्री डाह्याभाई व० पटेल : मैंने आपको अंग्रेजी मे बोलने के लिये नहीं कहा।

श्री चन्द्र शेखर : तो मैं यह कह रहा था कि इस आन्दोलन को चलाना है तो बुनियादी तौर पर दो-चार काम करने होंगे कृषि के क्षेत्र में। सहकारी आन्दोलन दो बातों की मांग करता है। एक तो खेत के ऊपर अधिकार किस का हो। खेत के ऊपर अधिकार जब तक खेती करने वाले का नहीं होता, जब तक बड़े बड़े खेतिहर लोग मौजूद हैं, इस मुल्क में जिन के पास हजारों एकड़ फार्म है, तब तक एग्रीकल्चर को-आपरेटिव के रास्ते में अड़चन पड़ी ही रहेगी। मैं इसके विवरण मे नही जाना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि इन सारी कठिनाइयों के बावजूद संगठन कर्ताओं को चाहिये, कार्यकर्ताओं को चाहिये कि गांव में जाकर बैठ कर लोगों को समझायें महात्मागांधी के जमाने में जिस तरह से स्वतन्त्रता संग्राम के रास्ते में अनेक अवरोध के बावजूद भी महात्मा गांधी जी ने एक एक किसान को समझाया कि तुम्हारा भला इसी मे है कि

[श्री चन्द्र शेखर]

अंग्रेजी राज को इस देश से बाहर निकालो। तो फिर क्या हुआ, महोदया, गांव का गरीब से गरीब आदमी भी जो बगैर पढ़ा लिखा था, जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वह भी सब से बड़े साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा हो गया। अगर आज सहकारी क्षेत्र में काम करने के लिए छोटे छोटे कार्यकर्ता मिलें जो गांव में जा कर और वहां पर बैठ कर बतलायें--- माननीय वाजपेयी जी और पटेल जी के दिलों में भले ही यह बात न हो, किन्तु उन की पार्टियां इसलिये विरोध करती हैं कि जिन लोगों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों के मन में यह बात बसी है कि जो प्रापर्टी रिलेशन कृषि क्षेत्र में स्वामित्व हैं, वे बदलने नहीं चाहियें ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : गलत बात है ।

श्री चन्द्र शेखर : अगर यह बात समझाई जाये तो यह सहकारी आन्दोलन एक राष्ट्रीय आन्दोलन बन सकता है। तो मैं माननीय डे साहब से अपील करूंगा कि अगर वे कृषि क्षेत्र में सहकारिता को फैलाना चाहते हैं, तो जो कृषि सुधार का काम उनकी दूसरी मिनिस्ट्री करती है उसके सहयोग लेने की बात करें। कभी कभी डे साहब बयान दे देते हैं, लेकिन मौलिक बातों को समझाने का साहस नहीं करते और दूसरे मिनिस्टर साहब से यह नहीं कह सकते कि इस कार्य में इस तरह की मौलिक कठिनाइयां हैं। इन मौलिक कठिनाइयों को दूर किये बिना हुकूमत सहकारी आंदोलन को केवल उसी सीमा तक चला सकती है, जिस सीमा तक छोटे छोटे कार्यकर्ता मिलकर गांव में जा कर लोगों में जागरण पैदा करें और उनको यह बतलायें कि छोटे छोटे किसान तब ही सफल होंगे, तब ही उनकी बुनियादी तरक्की होगी, जब वे मिल-जुल कर काम करेंगे। मुझे इस बात से हैरत होती है कि जब गांवों में इस प्रकार का आन्दोलन किया जाता है कि तुम्हारी जमीन छीनी जा रही है। मैं और सूबों की बात तो नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ७० फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है, तो ऐसी जोत से वे क्या पैदा कर सकते है और किस तरह से वे नई पद्धति द्वारा कोई चीज पैदा कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट और विकास खंड के लोग उन्हें सारे ढंग बतलाते हैं, लेकिन वे कभी इस बात को भी सोचते हैं कि इतनी छोटी जोत के ऊपर, जिसमें एक किसान अपने खाने तक के लिये अन्न पैदा नहीं कर सकता है, कैसे नये साधन का उपयोग करेगा ? वह इतनी छोटी भूमि के होते हुए कर्ज नहीं ले सकता पूंजी नहीं लगा सकता और खास कर नये वैज्ञानिक साधनों का उपयोग वह किसी तरह से भी नहीं कर सकता है। महोदया, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि प्रोफैसर मुकुटबिहारी लाल और श्री रामचन्द्रन् ने यह कहा कि इस चीज को राजनीतिक दलों का शैटिलकाक नहीं बनाया जाना चाहिये। अगर श्री डे साहब को यह गलतफहमी रही है तो आने वाले दिनों में और कठिनाई होने वाली है, इसको समझना चाहिये। यह मौलिक रूप से एक राजनैतिक सवाल है और इस सवाल को राजनीतिक स्तर पर सामना करना चाहिये और उसमें जो कठिनाइयां आयें उन कठिनाइयों को दूर करके इस आन्दोलन को आगे चलाना चाहिये ।

मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बहस पर बोलने का मौका दिया। माफ कीजिये, मैं अपनी एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह है कि दो-तीन अखबारों में कहीं यह छपा है कि मैं संयुक्त समाजवादी दल में हूं। मेरा इस दल से कोई संबंध नहीं है। मैं संयुक्त समाजवादी दल में शामिल नहीं हुआ हूं ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : आप का किस दल से संबंध है ?

श्री चन्द्र शेखर : मैं स्वतन्त्र हूं ।

شری پیارے لال کریل "طالب" :
(اتر پردیش) : جہاں تک اس پرستاو کا تعلق ہے - اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ جو یہ پتہ لگائے کہ اس دیش میں جو کوآپریٹیو تحریک ہے اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے اور آگے ہم اس کی ترقی کے بارے میں کیا قدم اٹھا سکتے ہیں - اس پرستاو کے سمبندھ میں بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جن کا اس سے کوئی سمبندھ نہیں ہے اور ہم اپنے راستہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں لیکن میں سب سے پہلے اس پرستاو کے بارے میں جو چیز کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سے کوآپریٹیو سوسائٹی بننی شروع ہوئی وہ اس مقصد سے بنائی گئی تھیں کہ ہمارے ملک میں جو غریب عوام ہیں جو چھوٹے درجہ کے لوگ ہیں ویکر سیکشن کے لوگ ہیں ہریجن ہیں پست اقوام ہیں بیک ورڈ کلاس کے لوگ ہیں اور اوسطاً درجہ کے لوگ ہیں نیچے اوسطاً درجہ کے لوگ ہیں ان کی مالی حالت بہتر بن سکے اور وہ کچھ ترقی کر سکیں - اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوآپریٹیو تحریک نے اس مقصد کو پورا کیا کہ نہیں - کہاں تک اس مقصد کو حاصل کیا گیا ہے - یہ ہمیں دیکھنا ہے - اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو اٹھایا جائے ان کو اوپر لایا جائے تاکہ زندگی کے تمام شعبوں میں وہ برابر کا حصہ لے سکیں - اس دیش میں اس طرح کا سوشلزم آئے کہ سارے طبقوں میں سوشلزم قائم ہو جائے مگر ہم کیا دیکھتے ہیں - ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوآپریٹیو تحریک کے چلتے ہوئے ساٹھ ستر سال ہو گئے مگر ابھی تک اس میں نمایاں کامیابی نہیں ہوئی جتنی کامیابی ہمیں اس میں حاصل ہونی چاہئے تھی وہ نہیں ہو سکی - اس میں کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے - کسی ایک فرقہ کا سوال نہیں ہے - یہ تو سارے دیش کا سوال ہے - ہو سکتا ہے کہ ہمارے شری دیا بھائی کی پارٹی کا چند باتوں میں ہم سے اختلاف ہو لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو جن سنگھ کی ہی کیوں نہ ہو سب یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوآپریٹیو تحریک کو بڑھاوا ملے - تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس تحریک کی ناکامی کا کیا کارن ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں ترقی نہیں کر سکے جب کہ دوسرے دیشوں نے ترقی کی ہے - ہمیں اس تحریک میں ترقی نہیں ملی ہے اس کا کوئی کارن ہے - سب سے بڑا کارن ہے کہ ہمارے دیش کے اندر ان لٹریسی کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے - ہمارے

[شری بھاورے لال کوریل (اترپردیش)]

دیش میں ناخواندہ اور ان پڑھ لوگ بہت ہیں جو کہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کوآپریٹیو سوسائٹی کو کیسے چلایا جانا چاہئیے - ان کا کسی قسم کا ذہن نہیں ہے - نتیجہ کیا ہوتا ہے - نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چالاک آدمی اپنے فائدہ کے لئے سوسائٹی قائم کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے لیکن غریب آدمی کو اس میں پھنسا دیتا ہے - چالاک آدمی غبن تو خود کرتا ہے اور غریب آدمی کو اس میں پھنسا دیتا ہے - اور سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں ان پڑھ لوگ ہیں جو کہ اس کے ممبر بنے ہوئے ہیں - اس کے پریذیڈنٹ بنے ہوئے ہیں - چالاک آدمی غریب آدمیوں کو ہریجنوں کو پریذیڈنٹ بنا دیتے ہیں - دیہات کے کسی ان پڑھ چودھری کو پریذیڈنٹ بنا دیتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد غبن کے معاملہ میں اس پر مقدمہ چلتا ہے - ایسے بہت سے کیسیز ہوئے ہیں اور ایسا کوئی بھی ضلع نہیں ہے - جہاں پر اس طرح کے کیسیز نہ چلتے ہوں - خرابیاں دوسرے کرتے ہیں اور سزا دوسرے پاتے ہیں - بدمعاشی دوسرے کرتے ہیں اور سزا دوسرے معصوم آدمی پاتے ہیں - یہی عام طور پر سب کوآپریٹیو سوسائٹیز میں ہوتا ہے -

دوسری کیا وجہ ہے ان سوسائٹیوں کی ناکامی کی ؟ ان سوسائٹیز کی ناکامی کا دوسرا کارن یہ ہے کہ ہمارے آفیسر جو ہیں وہ اس میں بے جا دخل دیتے ہیں - بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے افسر ہیں چاہے سپروائزر کو لے لیجئے - چاہے انسپکٹر کو لے لیجئے - وہ شروع میں ایک ہم بڑا جوش دیکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی بنانی ہے وہ سوسائٹی بنانی ہے اس گاؤں میں بنانی ہے - اس گاؤں میں بنانی ہے - اس کے لئے بنانی ہے اور اس کے لئے بنانی ہے مگر جب وہ سوسائٹی بن جاتی ہے اور سرکار سے روپیہ مل جاتا ہے تو وہ ننگا ناچ دکھاتے ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ روپیہ اس میں خرچ کیجئے اور ان سے دستخط کرا لیتے ہیں - وہ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں اور نہ وہ اکاونٹ رکھنا جانتے ہیں اور نہ رجسٹر میںٹین کرنا جانتے ہیں - اس لئے وہ ان افسروں کے چکر میں آ جاتے ہیں - آج کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں ایسے دو چار کیسیز نہ چل رہے ہوں - تو اس طرح ان سوسائٹیوں کے فیل ہونے کا مین کارن یہ ہے کہ ہمارے افسر ان غریبوں کی ناخواندگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح سے سوسائٹیز کو ختم کرتے ہیں -

اس سلسلہ میں تیسری سب سے بڑی رکاوٹ ایک اور ہے - مجھے افسوس ہے کہ تمام کمیشن بنے تمام کمیٹیاں بنیں مگر آج تک سرکار کی طرف سے کوئی کمیٹی ایسی نہیں بنی جو ان حالات کو معلوم کرتی اور ان وجوہات کو معلوم کرتی جن کی وجہ سے ہماری کوآپریٹیو تحریک آگے نہیں بڑھ رہی ہے - کوئی ایسی کتاب نہیں ہے - کوئی ایسی ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے کوئی ایسی کمیٹی کی رپورٹ نہیں ہے جس سے ہم جان سکیں کہ اس ناکامیابی کی وجہ کیا ہے - ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے آل انڈیا رورل کریڈٹ سروے کی جو ریزرو بنک آف انڈیا کی طرف سے سنہ ۱۹۵۵ء میں شائع ہوئی ہے - یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے اور میں یہ کہوں گا تمام ممبروں سے کہ وہ اس رپورٹ کو ضرور پڑھیں - جہانتک ان کوآپریٹیو سوسائٹیز کا تعلق ہے بہت سی باتیں اس رپورٹ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اور خاص طور پر یہ تین باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں جو میں نے بتائیں - جن کی وجہ سے ہمارا یہ آندولن ناکام رہا - میں آپ کی اجازت سے پیراگراف پڑھوں گا - یہ سوشل اسٹرٹیفیکیشن کے متعلق انہوں نے لکھا ہے -

"The existing rigid social stratification should not be forgotten. For centuries, landowners and tenants may live nearby but have no close intimacy for sympathetic understanding of their day-to-day needs. Nearness alone does not impart mutual knowledge. Again, close contacts among castes create an affinity which cuts across co-operative loyalties....Backward communities are tied to their old-world ceremonies, priests and caste rules. Their range of contacts is little. They are less susceptible to new ideas. They have little desire to improve their standard of life."

آگے چل کر یہ کہا ہے --

"The co-operative organization today contains middle class leadership of varying and conflicting interests. It is only in India one find....mill-owners, *rentier* landlords and traders being the leaders of co-operative organizations and yet we hear not a whisper from any quarter against this entry of inimical elements in the co-operative body."

ہم کہتے تو یہ ہیں کہ یہ چھوٹے آدمیوں کو بڑھانے کے لئے بلاتے ہیں مگر فائدہ کون اُٹھاتا ہے - اُونچی ذات کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں - چالاک لوگ فائدہ اُٹھاتے ہیں بڑے لوگ فائدہ اُٹھاتے ہیں - آگے ذات پات کے بارے میں یہ دیا ہوا ہے —

"The directors of (certain co-operative) societies are Kammas, Reddis, Brahmins (top communities in villages) and they do not take even on their staff members of any other communities. If a Reddi is the president of the society, all the members of the staff are Reddis. If the president is a Brahmin, all the members of the staff are Brahmins."

یہ کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہے - یہ تو ریزرو بنک آف انڈیا کی رپورٹ ہے - اس میں آگے پھر انہوں نے

[شری پیارے لال کریل "طالب"]

افسروں کے بارے میں بھی کہا ہے اور الٹریسی کے بارے میں بھی کہا ہے —

"The general lack of education and inadequacy of training are two features emphasized as very important by the Royal Commission on Agriculture (1928) as causes for the poor growth of co-operation in India. The Preliminary Report (1936) and the Statutory Report (1937) of the Reserve Bank of India emphasized that the lack of training in commercial banking methods was one of the main causes of the unsatisfactory record of co-operative credit in India."

اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سی باتیں کہی ہیں - آفیشل قسم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے —

OFFICIALDOM AND RURAL INDIA

" . . . Fully aware of my own lack of intimate knowledge of Indian village life, I began to realize that many of the Indian officials from Delhi on down through the State capitals to the villages themselves, brilliantly educated and competent in Western ways, were almost equally estranged in one way or another, from village India."

" . . . Though it is now a truly Indian Government, the people see the same officials in charge of administration, and often react with the same non-committal attitude as they previously used. But it is not all due to the people's attitude. Government offices are places of forms, unintelligible red tape and waiting-rooms that the uninitiated and uneducated feel it is best not to approach."

ہمارے کانسٹی ٹیوشن کا مقصد یہ ہے کہ بیک ورڈ کلاسز کو اوپر اٹھایا جائے مگر ان حالات کی وجہ سے نہ ہمارا کوآپریٹیو موومنٹ کامیاب ہو پاتا ہے اور نہ ہمارے بیک ورڈ کلاس کے لوگ آگے آ پاتے ہیں - اب کیا کرنا چاہئے ہم کو - سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دیش کے اندر الٹریسی بہت ہے - ستر پچہتر فی صدی لوگ ناخواندہ ہیں - ان کو پڑھانے کے کام میں ابھی ٹائم لگے گا - مگر کم از کم اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جو بڑے آفیشلس ہیں وہ ان کے پاس جائیں - چھوٹے آفیسرس تو ان سے پیسے لیں گے اور طرح طرح کی غلط فہمیاں ان کے اندر پھیلائیں گے - اس لئے بڑے آفیشلس ان کے پاس جائیں اور کم از کم ان کو اکاؤنٹس رکھنا سکھائیں اور یہ بتائیں کہ یہ پیسہ اس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح سے رجسٹر پر چڑھانا چاہئے - یہ تھوڑی سی کمرشیل ٹریننگ جو کوآپریٹیو سوسائٹیز کے اندر ہیں ان کو دی جائے تاکہ وہ اپنی خود حفاظت کرسکیں اور اگر کوئی ان کے ساتھ بےایمانی کرتا ہے اس کو وہ سمجھ سکیں - اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ جو الٹریسی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے -

اس کے علاوہ جو آفیشلس وہاں جائیں وہ یہ دیکھیں کہ کسی کوآپریٹیو

سوسائٹی میں چھوا چھوت کا برتاؤ تو نہیں ہوتا ہے اور اگر کسی سوسائٹی میں چھوا چھوت کا برتاؤ ہوتا ہو تو اس کو ختم کیا جائے - اس سوسائٹی کے آفیس بیررس اور دوسرے ممبران جو ہوں ان کو یہ تاکید کی جائے کہ اگر اس کے اندر چھوا چھوت کا برتاؤ ہوگا یا نیچے طبقہ کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا تو وہ سوسائٹی چل نہیں سکتی - اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے - جب تک چھوا چھوت رہے گی تب تک کسی فیلڈ میں کسی سفیر آف ایکٹیویٹی میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے- اس لئے سب سے پہلی چیز اس کوآپریٹیو مومنٹ کی ترقی کے لئے یہ ہے کہ چھوا چھوت کی بات جو دیہاتوں کے اندر ہے اس کو دور کیا جائے اور فارمنگ سوسائٹی بنائی جائیں - اس سے ہمارا پروڈکشن بھی بڑھے گا - ابھی آپ ایگریکلچرل سوسائٹی بناتے ہیں - آپ فارمنگ سوسائٹی بناتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے کہ ایکچول ٹلر آف دی سوائل کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے - ٹلر آف دی سوائل کو چاہے سوسائٹی ہو چاہے کوئی انڈیوزول بڑا کاشت کار ہو صرف مزدور ہی سمجھتا ہے - بجائے اس کے کہ اس کو اپنے ساتھ لے اور برابر پر بٹھائے - میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی کوآپریٹیو سوسائٹیز بنیں جتنی بھی ایگریکلچرل سوسائٹیز بنیں ان میں یہ ہونا چاہئے کہ ۵۰ فی صدی یا اس سے کچھ کم ممبر جو ہوں وہ ایکچول ٹلر آف دی سوائل ہوں یعنی وہ ایک ہونے چاہئیں جو کہ اپنے ہاتھوں سے کھیتی کرتے ہیں یا کوئی دست کاری کرتے ہیں - اس طرح جو آدمیوں کو آپ ممبر بنائیں انہیں کے ہاتھ میں آپ انتظام دیجئے -

اسی طرح سے آج سینکڑوں بیگھ زمین بے کار پڑی ہوئی ہے - اس کے لئے آپ کھیتر مزدوروں اور ایسے آدمیوں کی کوآپریٹیو سوسائٹیز بنائیے - ایسے لوگوں کی کوآپریٹیو سوسائٹی بنائیے جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے - ان کو آپ سیکڑوں ایکڑ زمین دیجئے اور ان کی ایک سوسائٹی بنا دیجئے - پھر آپ ان سے کہئے کہ آپ سوسائٹی کے ذریعہ یہ جو بے کار زمین پڑی ہوئی ہے اس کو کاشت میں لائیے - اگر آپ ایسا کرینگے تو اس سے آپ کا پروڈکشن بھی بڑھیگا - اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھئے کہ اس میں کسی کو دخل دینے کی گنجائش مت رکھئے -

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. I am sorry.

شری پیارے لال کوریل "طالب" :

میں ایک منٹ صرف آپ سے اور لوں گا -

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you have said many things after your time limit. Fifteen minutes is the time given.

شری پیارے لال کریل دد طالب دد :

میں آپ کے ذریعہ یہ نویدن کرونگا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں امید ہے کہ سرکار ان پر غور کریگی - میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا - مگر جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پر بھی اگر عمل کیا گیا تو ہمارے کوآپریٹیو موومنٹ کو حقیقت میں فائدہ ہوگا اور غریب عوام جو اس دیش میں ہیں وہ آگے بڑھ سکینگے اور فوڈ پروڈکشن بھی ہمارے دیش کا بڑھ سکیگا -

†[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' : (उत्तर प्रदेश) : जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है, इसका मकसद यह है कि एक ऐसी कमेटी बनायी जाये, जो कि यह पता लगाए कि इस देश में जो को-आपरेटिव तहरीक है, उसमें कितनी तरक्की हुई है और आगे हम इसकी तरक्की के बारे में क्या कदम उठा सकते है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने ऐसी बातें कहीं हैं, जिनका इससे कोई संबंध नही है और हम अपने रास्ते से कुछ हट गए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस प्रस्ताव के बारे में जो चीज कहनी चाहता हूं, वह यह है कि जब से को-आपरेटिव सोसाइटी बननी शुरू हुई, वह इस मकसद से बनायी गयी थीं कि हमारे मुल्क में जो गरीब अवाम है, जो छोटे दर्जे के लोग हैं और जो औसतन दर्जे के लोग हैं, नीचे औसत दर्जे के लोग हैं, उनकी माली हालत बेहतर बन सके और वो कुछ तरक्की कर सकें। अब देखना यह है कि हमारे मुल्क में को-आपरेटिव तहरीक ने इस मकसद को पूरा किया या नहीं। कहां तक इस मकसद को हासिल किया गया है? यह हमें देखना है। इस तहरीक का मकसद यह है कि गरीबों को उठाया जाए, उनको ऊपर लाया जाए, बाकी जिन्दगी के तमाम शोबों में वो, बराबर का हिस्सा ले सकें। इस देश में इस तरह का सोशलिज्म आए कि सारे तब्कों में सोशलिज्म कायम हो जाए, मगर हम क्या देखते हैं? हम यह देखते है कि को-आपरेटिव को चलते हुए ६०-७० साल हो गए, मगर अभी तक उसमें नुमायां कामयाबी नहीं हुई, जितनी कामयाबी उसमें हासिल करनी चाहिये थी, वह नही हो सकी. इसमें कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है किसी एक फिर्के का सवाल नहीं है, तो यह एक सारे देश का सवाल है। हो सकता है कि हमारे श्री डाह्याभाई की पार्टी का चन्द बातों मे हमसे इख्तिलाफ हो, लेकिन जहां तक हमारा ख़याल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जनसंघ की ही क्यों न हो, सब यही चाहते है कि इस तरह की को-आपरेटिव तहरीक को बढ़ावा मिले। मै यह नही समझता कि इस तहरीक की नाकामयाबी का क्या कारण है और क्या वजह है कि अभी तक इसमें तरक्की नहीं कर सके, जबकि दूसरे देशों में तरक्की की है। हमें इस तहरीक में तरक्की नहीं मिली है। इसका कोई कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के अन्दर इल्लीट्रेसी की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हमारे देश में नाख्वान्दा और अनपढ़ लोग बहुत हैं। जो कि यह नहीं जानते है कि को-आपरेटिव सोसाइटी को कैसे चलाया जाना चाहिये। उनका किसी किस्म का जहन नही है, नतीजा क्या होता है। नतीजा यह होता है कि एक चालाक आदमी अपने फायदे के लिये सोसाइटी कायम करता है और फायदा उठाता है, लेकिन ग़रीब आदमी को उसमें फसा देता है। चालाक आदमी गबन तो खुद करता और गरीब आदमी को उसमें फंसा देता है और सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि हमारी सोसाइटीज में अनपढ़ लोग हैं, जोकि इसके

†[ ] English transliteration.

मेम्बर बने हुए हैं इसके प्रेज़िडेंट बने हुए हैं। चालाक आदमी गरीब आदमियों को, हरिजनों को प्रेज़िडेंट बना देते हैं। दहात के किसी अनपढ़ चौधरी को प्रेजिडेंट बना देते हैं और कुछ अर्से के बाद गबन के मामल में उस पर मुकदमा चलता है। ऐसे बहुत से केसेज हुए हैं और ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर इस तरह के केसेज न चलते हों। खराबियां दूसरे करते हैं और सज़ा दूसरे पाते हैं। बदमाशी दूसरे करते हैं और सज़ा दूसरे महसूम आदमी पाते हैं। यही आम तौर पर सब को-आपरेटिव सोसाइटीज़ में होता है।

दूसरी क्या वजह है इन सोसाइटीज की नाकामी की। इन सोसाइटीज की नाकामी का दूसरा कारण यह है कि हमारे अफसर जो हैं, वो इसमें बेजा दखल देते हैं। बहुत से ऐसे छोटे छोटे अफसर हैं, चाहे सुपरवाइज़र को ले लीजिये, चाहे इन्सपेक्टर को ले लीजिये, वो शुरू में चाहे एकदम बड़ा जोश दिखाते हैं और यह कहते है कि यह सोसाइटी बनाते हैं, वो सोसाइटी बनानी है, इस गांव में बनानी है, उस गांव में बनानी है। उसके लिये बनानी है और इसके लिये बनानी है, मगर जब वह सोसाइटी बन जाती है और सरकार से रुपया मिल जाता है, तो वो नंगा नाच दिखाते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि यह रुपया इसमें खर्च कीजिये और उनसे दस्तखत करा लेते हैं. वो बेचारे अनपढ होते हैं और ना वो एकाऊंट रखना जानते हैं और न रजिस्टर मेनटेन करना जानते हैं, इसलिए वो इन अफसरों के चक्कर में आ जाते हैं; आज कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ऐसे दो-चार केसेज़ न चल रहे हों। तो इस तरह इन सोसाइटियों के फेल होने का मेन कारण यह है कि हमारे अफसर इन गरीबों की नाख्वांदगी का फ़ायदा उठाते है और उनकी महसूमियत का फायदा उठा कर खुद फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह से सोसाइटीज़ को खत्म करते हैं।

इस सिलसिले मे तीसरी सबसे बड़ी रुकावट एक और है, मुझे अफसोस है कि तमाम कमीशन बने, तमाम कमेटियां बनी, मगर आज तक सरकार की तरफ से कोई कमेटी ऐसी नहीं बनी, जो कि इनहालात को मालूम करती और उन वजूहात को मालूम करती जिनकी वजह से हमारी को-आपरेटिव तहरीक आगे नहीं बढ़ रही है। कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है कोई ऐसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं जिससे हम जान सकें कि इस नाकामयाबी की वजह क्या है? एक हमारे पास रिपोर्ट है आल-इंडिया रूरल क्रैडिट सर्वे की, जो रिज़र्व बक आफ इंडिया की तरफ से १९५५ में शाया हुई है, यह बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और मैं यह कहूंगा कि तमाम सदस्यों से कि वो इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें जहां तक उन को-आपरेटिव सोसाइटीज़ का ताल्लुक है, बहुत-सी बातें इस रिपोर्ट ने हमारे सामने रक्खी हैं और खास तौर पर ये तीन बातें हमारे सामने रक्खी हैं, जो मैंने बतायी हैं। जिनकी वजह से हमारा यह आन्दोलन नाकाम रहा। मैं आपकी इजाज़त से पैराग्राफ पढ़ूंगा। यह सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के मुतल्लिक उन्होंने लिखा है :—

"The existing regid social stratifi- may live nearby but have no close cation should not be forgotten. For centuries, landowners and tenants may live nearby but have no close intimacy for sympathetic understanding of their day-to-day needs. Nearness alone does not impart mutual knowledge. Again, close contacts among caste create an affinity which cuts across co-operative loyalties....Backward Communities are tied to their old-world ceremonies, priests and caste rules. Their range contacts is little. They are less susceptible to new ideas. They have little desire to improve their standard of life."

आगे चल कर यह कहा है :

"The co-operative organisation today contains middle class leadership

[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब']

of varying and conflicting interests. It is only in India one finds....mill-owners, *rentier* landlords and traders not a whisper from any quarters against this entry of inimical elements in the co-operative body."

हम कहते तो यह हैं कि यह छोटे आदमियों को बढ़ाने के लिए बनाते हैं, मगर फायदा उठाते कौन हैं ? ऊंची ज़ात के लोग फायदा उठाते हैं। चालाक लोग फायदा उठाते हैं। बड़े लोग फायदा उठाते हैं।

आगे ज़ात-पात के बारे में यह दिया हुआ है :

"The directors of (certain co-operative) societies are **Kammas**, Reddis, Brahmins (top communities in villages) and they do not take even on their staff members of any other communities. If a Reddi is the president of the society, all the members of the staff are Reddis. If the President is a Brahmin, all the members of the staff are Brahmins."

यह कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। यह तो रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें आगे फिर आफिसर्स के बारे में भी कहा है और इल्लीट्रेसी के बारे में भी कहा है :

"The general lack of education and inadequacy of training are two features emphasized as very important by the Royal Commission on Agriculture (1928) as causes for the poor growth of co-operation in India The Preliminary Report (1938) and the Statutory Report (1937), of the Reserve Bank of India emphasized that the lack of training in commercial banking methods was one of the main causes of the unsatisfactory record of co-operative credit in India."

इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। आफीशियलडम के बारे में भी उन्होंने यह जिकर किया है :

OFFICIALDOM AND RURAL INDIA

" . . . Fully aware of my own lack of intimate knowledge of Indian village life, I began to realise that many of the Indian officials from Delhi or down through the State capitals to the villages themselves, brilliantly educated and competent in western ways, were almost equally estranged in one way or another, from village India."

". . . . Though it is now a truly Indian Government the people see the same officials in charge of administration, and often react with the same non-committal attitude as they previously used. But it is not all due to the people's attitude Government offices are places of forms, unintelligible red tape and waiting-rooms that the uninitiated and uneducated feel it is best not to approach."

हमारे कांस्टीट्यूशन का मकसद यह है कि बैकवर्ड क्लासिज को ऊपर उठाया जाये मगर उन हालत की वजह से न हमारा को-आपरेटिव मूवमेंट कामयाब हो पाता है और न हमारे बैकवर्ड लोग आगे आ पाते हैं। अब क्या करना चाहिए हमको ? सबसे पहली बात यह है कि इस देश के अन्दर इल्लीट्रेसी बहुत है। सत्तर-पिछत्तर फी सदी लोग नाखवांदा हैं, उनको पढ़ाने के काम में अभी टाइम लगेगा मगर कम-अज़-कम इतना किया जा सकता है कि जो बड़े आफिशियल्स हैं वो उनके पास जाएं छोटे-छोटे आफीसर्स तो उनसे पैसा लेंगे और तरह तरह की गलत-फहमियां उनके अन्दर फैलायेंगे। इसलिए बड़े आफिशियल्स उनके पास जायें और कम-अज़-कम उनको एकाउंट रखना सिखाएं और यह बताए कि यह पैसा किस तरह से खर्च किया जाता है और उसको इस तरह से रजिस्टर पर चढ़ाना चाहिए। यह थोड़ी सी कमर्शियल ट्रेनिंग जो को-आपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर हैं, उनको दी जाएं ताकि वो अपनी खुद हिफाज़त कर सकें। और अगर कोई उनके साथ बेईमानी करता है तो उसको वो समझ सकें। उसके साथ साथ उनके अन्दर यह जो इल्लीट्रेसी है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए।

इसके अलावा जो आफीशियल्स वहां जाएं वो यह देखें कि किसी को-आपरेटिव सोसाइटी में छुआछूत का बर्ताव तो नहीं होता है, अगर किसी सोसाइटी में छुआछूत का बर्ताव होता हो तो उसको खत्म किया जाए । उस सोसाइटी के आफिस-बेयरर्स और जो दूसरे मेम्बरान हों उनको यह ताकीद दी जाए कि अगर इसके अन्दर छुआछूत का बर्ताव होगा या नीचे के तबके के लोगों के साथ इम्तयाज़ी मलूक होगा तो वो सोसाइटी चल नहीं सकती । इस पर ज्यादा ज़ोर देने की जरूरत है । जब तक छुआछूत रहेगी तब तक किसी फील्ड में किसी स्फेयर आफ एक्टीविटी में तरक्की नहीं हो सकती । इसलिए सब से पहली चीज इस को-आपरेटिव मूवमेंट की तरक्की के लिए यह है कि छुआछूत की बात जो देहातों के अन्दर है उसको दूर किया जाए और फार्मिंग सोसाइटीज बनायी जाएं । इससे हमारा प्रोडक्शन ही बढ़ेगा । अभी आप एग्रीकल्चर सोसाइटीज बनाते हैं आप फार्मिंग सोसाइटीज बनाते है मगर होता क्या है कि एक्चुअल टिलर्स सही मायने में हल चलाने वाला, उसका कोई हाथ नहीं होता है । टिलर्स आफ दी सॉयल चाहे कोई इण्डीविजुअल बड़ा काश्तकार हो, मजदूर ही समझता है कि बजाय उसके अपने साथ ले और बराबर पा ले । मैं यह कहूंगा कि जितनी भी को-आपरेटिव सोसाइटीज बनीं जितनी भी एग्रिकल्चरल सोसाइटीज बनीं उसमें यह चाहिए कि ५० फी सदी या उससे कुछ कम मेम्बर जो हों वो एक्चुअल टिलर्स आफ दा सॉयल हों यानी वो लोग होने चाहिएं जो कि अपने हाथों से खेती करते है या कोई दस्तकारी करते हैं । इस तरह जिन आदमियों को आप मेम्बर बनाएं उन्हीं के हाथ में आप इन्तज़ाम दीजिए ।

इसी तरह से आज सैंकड़ों बीघे जमीन बेकार पड़ी हुई है । इसके लिए आप खेतिहर मजदूरों और ऐसे आदमियों की को-आपरेटिव सोसाइटीज बनाइए । ऐसे लोगों की को-आपरेटिव सोसाइटीज बनाइए जिनके पास कोई जमीन नहीं है । उनको आप सैकड़ों एकड़ जमीन दीजिए । और उनकी एक सोसाइटी बना दीजिये । और उनको फिर उनसे आप कहिए कि आप सोसाइटी के जरिए यह जो बेकार जमीन पड़ी हुई है, उसको काश्त में लाइए । अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा । उसमें एक बात का ज़रूर ख़याल रखिए कि उसमें किसी को दखल देने की गुंजाइश मत रखिए ॥

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. I am sorry.

श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' : मैं एक मिनट आपसे सिर्फ और लूंगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you have said many things after your time limit. Fifteen minutes is the time given.

श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' : मैं आपके जरिए यह निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं, उम्मीद है कि सरकार उन पर गौर करेगी । मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर मैंने जो बातें कही हैं अगर उन पर भी अमल किया गया तो हमारे को-आपरेटिव मूवमेंट को हकीकत को फायदा होगा और गरीब अव्वाम जो इस देश में हैं वो आगे बढ़ सकेंगे और प्रोडक्शन भी हमारे देश का बढ़ सकेगा ।]

SHRI D. THENGARI (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, in the first place, I think I must clarify the position of Jan Sangh because there was reference to it in the speech of our friend, Mr. Chandra Shekhar. Mr. Chandra Shekhar was vehement without being logical and I can tell him that his vehemence was based upon ignorance of Jan Sangh's manifesto. I do not know whether he would like to go through the manifesto of Jan Sangh because once he understands what is Jan Sangh he would be deprived of his 'holier than thou' attitude which is thoroughly unjustified. That might embarrass him. I

[Shri D. Thengari]

must tell him that though he may be quite happy with his own paradise, the position of Jan Sangh is different from what he thinks it to be. Now, unlike the Swatantra Party, the Jan Sangh stands for land ceiling, but unlike the communists the Jan Sangh is opposed to collectivisation. Jan Sangh is all for the co-operative movement. It is also not in favour of co-operative farming simply because, as our communist friend here has just pointed out, collective farming is calculated to be a step ahead in the direction of collectivisation. I think our friend, Mr. Chandra Shekhar, has mistaken co-operation for coercion and the co-operative movement for collectivisation. That is unjustified. We are all in favour of co-operation. At the same time, we will not tolerate collectivisation and particularly this subject has a practical aspect also. It should not be merely a doctrinaire discussion. It has a practical aspect and that is that agriculture is the food-giving industry. It is the biggest industry of the land and no adventurism in the name of any doctrine can be permitted, can be tolerated in this vital industry of our country. Therefore, while opposing collectivisation we stand for land ceiling. Thus we have differentiated and distinguished our stand from both Swantantra on the one hand and communists on the other.

Now, coming to the Resolution, the subject-matter of the Resolution is very important because, as I said just now, it deals with the biggest and the food-giving industry of the country. It has been our feeling that in all the consecutive Plans agriculture has been discriminated against, so that we have not spent as much on agriculture as we ought to have done. Therefore, we are of opinion that henceforth more attention should be paid to agriculture, particularly by the Planning Commission, so that our *kisans* should be able to avail themselves of credit facilities not merely for production but also for consumption, not on the strength of their borrowing capacity but on the strength of their genuine needs. Unless that is done our *kisan* will not be enthused, will not be inspired to conduct his operations and give us greater production.

So far as the Resolution is concerned, while I agree entirely with the sentiments of the Mover, I think rural life cannot be compartmentalised. There are various aspects of rural life which are inter-related. They cannot be isolated and, therefore, it is necessary to take an integrated view of the entire rural life. For example, I agree with the Mover when he says that there are three aspects, *i.e.*, land, labour and capital, and that agricultural co-operatives deal mainly or only with the capital aspect of it. Now, how can we isolate the capital aspect from the other aspect, that is, labour? There are millions upon millions of landless labourers and we know that their difficulties, their maladies have had no remedy so far. I have experience myself. In order to give relief to agricultural workers, we tried to implement the Minimum Wages Act and some other Acts, but these Acts could not provide proper relief to landless labourers. Are they to form their own labour co-operatives or trade unions or should some subsidiary industries be started in the rural areas for their benefit? All these are interlinked, inter-related problems and, therefore, to consider any one aspect of rural life in isolation would be doing injustice to the integrated view of rural life.

There is another aspect of it which is also equally important. The Mover has referred to the role of the bovine species in our rural life, particularly in the agrarian economy. The bovine species have a very important role to play. It is unfortunate that this aspect has escaped the attention of the Government. Otherwise, the Government would have already banned, as was demanded, cow slaughter and the slaughter of the

bovine species. I remember that on this particular point the biggest ever petition submitted to the head of a State was submitted to our President a few years ago, but the entire thing was put in cold storage. It was very kind of the Mover that he has referred to the bovine species. Also, he tells us that we have got the lowest yield per annum from a cow, which is very unfortunate. Therefore, I take this opportunity of requesting the Government to be more serious about this matter, to legislate on the banning of cow slaughter and the slaughter of the bovine species and allow the bovine species to play the important role that it is designed to play.

Much has been said about the absence of co-operation. It has been aptly said by one authority that in India there is no co-operation in the co-operative movement. That is true. As a matter of fact, for the success of the co-operative movement it is necessary that a particular psychological environment should be created. I must say that the co-operative mind should precede the co-operative movement. That is what happened in the Scandanavian countries where the co-operative movement has been a great success. Now, we have put the cart before the horse. Probably there was no other alternative. Now, appropriate steps should be taken to create that environment and that would be a subject-matter not of any particular Party. There again, some co-operative effort, wherein all should put their shoulders together, would be required.

As I said, the subject-matter of this Resolution is very important. It is very urgent. It cannot allow, it cannot admit of any dilatorw tactics. While agreeing with the sentiments of the Mover, I must say that because I am in entire agreement with the objective of the Resolution, I oppose the Resolution because, as has already been experienced by many of us, by all of us, the appointment of a committee is just only another way of postponing the matter. If you do not want to expedite a matter, appoint a committee. Delay would naturally be there. Because I want that the matter should be expedited and also because I think that we are already having sufficient data on the matter, I feel that there should be no appointment of a committee. Therefore, I oppose the Resolution. At the same time, I think that even without the appointment of a committee, the matter can be expedited.

Thank you.

SHRI M. GOVINDA REDDY: (Mysore): Madam, I wish to support the resolution but with a slight change that the Committee that the Mover wishes to be appointed may not be confined only to the Members of Parliament. It may be enlarged to include other people qualified to contribute to the success of such a Committee.

Co-operation, Madam Deputy Chairman has been in recent years all-engrossing. It has entered almost every field of our economic activity. Co-operation has entered the field of credit and finance entered the field of manufacture and craft, entered the field of farming, storing, marketing and even labour contracts, entered the field of industry, and what not. Government have given every encouragement for the development of this movement without let or hindrance. They have neither spared pains nor money in developing the movement. That is why we have several co-operative corporations also. Now if for no other reason than this that this has become an all-engrossing movement wherein Government have put in hundreds of crores of rupees a Committee is necessary to go into the question of examining how this movement is now progressing. I do not mean to say that Government is not keeping a watch over the progress of the movement. Government are keeping a watch over the progress of the movement. I think the Minister.

[Shri M. Govinda Reddy.]

when it comes to his turn to reply, will say that more than 8 or 10 study teams are going to study the different aspects of the co-operative movement. They are watchful, but what I mean to say is that a new look has to be given to the co-operative movement. Generally what is wrong with us is that the intellectuals and most of our administrators are composed of urban elements and they are shaping the movement whereas practical knowledge should do so. We think of evolving schemes which according to us work in the best interests of the rural community. When we come to agriculture particularly, the schemes that the Government have devised in agriculture and the steps that they have taken, although all of them are well meant, do not yield the expected results, do not yield the maximum results because these schemes are not evolved with the eye of the farmer. They are not worked with the eye of the farmer. Those people responsible for framing these schemes are not people who have got intimate experience of agriculture. They have no intimate knowledge of rural conditions. Take the Food Ministry. Take the Agriculture Ministry. Take even the Planning Commission. How many of them are there who are farmers' sons? In the Planning Commission we do not have even one man who has got intimate knowledge of rural conditions. That is the same with the Agriculture Ministry. So when without knowing the actual conditions we begin to put in a scheme, naturally it cannot be expected to give the maximum results. That has been the unfortunate thing with all our rural administrations and much more so with our agricultural co-operatives. I will just point out one or two aspects as to how this movement can be reoriented.

Now we are forming co-operative societies mostly in the conventional manner. We allow the people interested in the co-operative movement to form a society, a consumers' co-operative society or a producers' co-operative society, like that, wherever people are willing to come forward to form a co-operative society, and then we allow it to be run according to the Co-operative Societies Registration Act. There we are. We have not even taken care—of course it is a State subject—to see that proper checks and balances are introduced. The Co-operative Societies Registration Act has a hundred loopholes, and the administering authority has no control over those who are running the co-operative societies so that in case of misappropriation and mismanagement the administration could easily haul them up in the court. Now of course the States have become alive to it after losses of several lakhs of rupees—crores of rupees I should say in the whole country, and sometimes in one society alone lakhs of rupees. Now they are amending the Co-operative Societies Registration Act. It is all for the good. The lines which I want to suggest, which can give a reorientation to the co-operative societies are in consonance with the rural conditions. For instance, if one studies the condition of the farmers, the farmers who were giving milk, distributing milk freely to those who did not have milch cattle such as teachers, clerks, police and such others in the villages, today do not have milk themselves. In my own family when I was a boy of 12, I remember we were boiling milk in such a big cauldron that we were distributing it in 'lotas' and 'chembus' to teachers and others freely. But today we do not have milk in our own house.

AN. HON. MEMBER: I think Mr. Sri Rama Reddy has.

SHRI M. GOVINDA REDDY: He has a dairy. But that will be more true in his own house than in the village. That is very common. In these days even the boys and girls and the babies cannot have milk. Today it is hard to get milk. You may

get it in Bangalore but not in small villages. Ghee is a thing which has become a scarcity. Why has this condition come to prevail when milk was freely flowing like water in villages before? That is because there is no fodder. There is no encouragement for cattle-breeding. It is for the co-operators to step in and see what can be done in order to solve this problem. We want our younger generation to grow strong at least. We did not have those facilities of getting good nourishment. In our day we should see that all the babies that are born get at least enough milk. In the villages and in the rural communities they do not have anything nourishing except milk, and that too they do not have now. So the Government can now send somebody, some expert—I mean not a dairy expert but somebody who knows the rural conditions—to suggest where exactly, at what centre, a milk co-operative society can be set up.

Similarly with regard to fodder, almost every farmer feels the difficulty of getting fodder. Much of the land is now coming under cash crop. I do not say it is bad. It is good But there must be some way devised of making the farmer grow more fodder or get more fodder. With the very shortsighted policy of the Government more and more forests are being reclaimed for agricultural purposes, which is not giving any benefit to the country but which is doing great damage, great harm to the farmer. That is because the fertility of the soil is washed away. There is soil erosion, and then the forests which were supplying fodder—that source is now removed from the village cattle. Therefore, you do not have fodder for the farmers' cattle. Therefore, there are not many cattle.

There is another aspect. We cannot depend upon tractor cultivation. Everybody is crying for tractors. Tractors are useful only for limited purposes. Where we reclaim fresh land tractor is useful. Where we have large tracts under co-operative farms or collective farms tractors are useful. But tractors are not useful for small plots. I had a talk with an American expert, who is a United Nations expert, who said that in India tractor cultivation was not beneficial excepting for turning up fresh land. That is because in India the humus is only up to about three inches in the soil. So only for about three to five inches the soil must be turned over. If we turn over it deeper, it loses its fertility. Therefore he advised against tractor cultivation except in fresh land. So we have to depend upon bullock power for small ploughs—the small ploughs can be drawn by bullock—until we are in a position to devise small engines. But where is the bullock power available? The very few cattle-rearing experts are now discouraged to rear cattle. Therefore, the cattle wealth is dwindling. It is for the co-operators now to think that cattle-breeding farms on co-operative lines can be started. Where is that to be done? And then the farmers' produce should be collected and marketed. Now, we have huge marketing societies. I think the Minister will now come out with facts and figures to show how many marketing societies are functioning in the country. But these marketing societies are only in very big cities. But when a farmer grows some small quantities of his commodities, then how are these small quantities to be collected, pooled and then marketed? Now for lack of this arrangement, the farmer is not getting his surplus farm produce marketed properly. It is for the co-operators to have farming societies in order to help the farmer to market these small quantities The Government instead of subsidising each and every sundry co-operative society by giving it management charges, this and that, can spend all the moneys for some research work—if you may call it so—and see that agricultural societies are established in order to promote the peasant's activities and to help him in these matters.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken 15 minutes.

SHRI M. GOVINDA REDDY: We used to hear a few years ago—there was a huge cry in the land about agricultural service co-operatives. We have not seen many service co-operatives coming into existence. We are generally a nation of *aarambha suras*, and so many people were saying that they would have so many things. Well, what has happened to the service co-operatives? I would like to ask the Minister of Agriculture. Now, for ten or fifteen villages, a small irrigation co-operative society may be started. I have seen in the West; there three or four farmers join together or ten or fifteen farmers join together; some villagers join together. And they form a co-operative society just for irrigation purpose. They mutually co-operate with each other. Then for supplying drinking water, for supplying gas, for supplying power, they have small co-operative societies. If the mind is applied, there are hundreds of other ways, original ways, by which we can form these co-operative societies in order to help the rural population. At least in order to do this work a Committee is necessary. I think the Minister will accept the principle of this Resolution.

Thank you for showing indulgence to me.

شری عبدالغفور (پنجاب) : مہودیہ ڈپٹی چیرمین - یہ سجھاؤ جو ہاؤس کے سامنے آیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کا تعلق نہ صرف کسانوں سے ہے بلکہ سارے دیش کی اُنتی اس پر نربھر ہے - آج اس بات کی چرچا ہے کہ ریولیوشن ہمارے دروازہ پر بڑے زوروں سے تھپکیاں دے رہا ہے اور وہ ریولیوشن کیوں آئے گا اس لئے کہ دیش کے ان کے مسئلہ کو ، ان کی سمسیا کو حل نہیں کر سکا - میں اس وقت ناگپور میں موجود تھا یہ حیثیت اُل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ممبر ہونے کے ناتے جس میں یہ کوآپریٹیو فارمنگ کی چرچا ہوئی - میں ان لوگوں میں تھا جو اس کی حمایت کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے شکوک کا اظہار بھی کہ کس ڈھنگ سے اس کو ہمارے دیش میں سرکار بنانا چاہتی ہے - اس پر غور کیا - اس سے پیشتر کہ میں اس سمسیا کی طرف جاؤں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جب انگریز گیا تو ہمارے دیش کے لوگوں کی حالت کیا تھی - ہمیں کتنا ان ودیشوں سے ملگانا پڑا اور جب کہ ہم یوجناؤں پر یوجناؤں چلائے جاتے ہیں بنائے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ہاؤس کا جو خیال تھا سب طرف سے سہکاری کھیتی باڑی پر زوروں سے تائید کی گئی - تقریباً تمام پارٹیوں نے اس کی بڑی مہما اور بڑی چرچا کی - اگر ہم اس بات کی چرچا کریں - بابو کہا کرتے تھے کہ زیادہ آنکڑے نہ بتاؤ لیکن آج کی حکومت ساری چلتی ہے وہ آنکڑوں کے زور پر ہی چلتی ہے اور پلان کرتی ہے - اگر وہ قابو نہ کر پائے کہ ہندوستان میں بچے زیادہ پیدا نہ ہوں - کہتے ہیں ۳۰ فی صدی بعض لوگ کہتے ہیں ۲۵ فی صدی آبادی ہماری بڑھ گئی

والا تانگے والا آج جو بھاؤ بمبئی میں
ہے ۷۰ روپئے سے زیادہ من گندم بک
رہی ہے - کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ
اچھی طرح سے اپنی زندگی آگذر بسر
کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال
سکتا ہے - آج ہم اس مہنگائی کے
مقابلہ میں لڑنا سرکاری ملازموں کو
اور بھتہ دے سکتے ہیں - مہنگائی
کا الاونس دے سکتے ہیں - جس سے
دیش کے دیو کو بھوک کے دیو سے بچا
سکیں - میں ایسا محسوس کرتا
ہوں کہ آج حالت اس پہلی حالت
سے چاہے وہ کوآپریٹو کے حق میں
جلھوں نے یہاں پر چرچا اسی وجہ
کی ہو اور میں نہیں جانتا کہ
میں مہابلی مانتا ہوں سورگیہ
سردار پٹیل کو لیکن میں دیا بھائی
پٹیل کو ایسا نہیں مانتا کہ وہ اتنے
بڑے ہنومان ہیں کہ سب پارٹیاں
چاہے وہ کوآپریٹو فارمنگ ہوں وہ
سب کی سب فیل ہو جائیں -
کیوں کہ دیا بھائی پٹیل اور ان کی
سوتنتر پارٹی جس کو جنم لئے پورے
پورے آٹھ دن نہیں ہوئے - وہ اتنی
مضبوط ہو گئی ہے کہ باقی سب
پارٹیاں - چاہے چندر شیکھر کی
پارٹی ہو کانگریس کی پارٹی ہو
سوشلسٹ کی پارٹی ہو وہ سب فیل
ہوگئیں - اس کے مقابلہ میں کہاں کا
طوفان آگیا کہ اس نے سب کو اور آپ کو
فیل کر دیا - جب آپ اس کی تہہ میں
جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ
یہ ہوجنا بہت پہلے ناگپور میں
پرستاؤ پاس کرنے سے بھی پہلے کی
ہے - ٹھیک ہے آبادی بڑھ گئی ہوگی -
بھن بھائیوں کو ترس کچھ نہ آیا ہوگا
اس سرکار کی کمزوریوں پر کہ اس کے
پاس سادھن نہیں ہیں کہ اتنے زیادہ
بچے پیدا ہو جائیں اور اتنی ہی
خوراک بھی پیدا ہوتی جاتی - لیکن
بہر حال کانگریس سرکار نے بڑا دعویٰ کیا
اور یہ کہا کہ ہماری پیداوار دیش
میں بڑے اوروں سے بڑھ رہی ہے اور
اس وقت یہ کہا کہ ہم اتنے سیڈ فارم
اتنے ہم ٹیوب ویل لگا رہے ہیں کہیں
بھاکڑہ کی چرچا ہوئی کہیں داموودر
ویلی کی چرچا ہوئی کہیں اور ڈیمس
کی چرچا کی گئی - لیکن حالت کیا
ہے - میں ہی نہیں دیکھتا آپ بھی
دیکھتے ہیں - آپ ہی نہیں دیکھتے
بلکہ سارا سنسار دیکھتا ہے - وہ
ہندوستان جو دوسروں کے لئے رام راجیہ
کی بات نہیں کرتا - میں چندر گپت
کے زمانہ کی بات نہیں کرتا میں
مغل امپائر کی بات کرتا ہوں - میں
مغل امپائر کی بات جب انگریزوں نے
یہاں دخل کیا اس کی بات کرتا ہوں -
اس سے پہلے بھوکے لوگ ہوتے تھے وہ
گنگا میں پیاری گنگا کی وادی میں
آتے تھے اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے
تھے - لیکن آج حالت کیا ہے - کیا
سوشلزم کا دعویٰ دار ملک وہ ملک جو
کہتا ہے کہ ہم سوشلزم لانا چاہتے ہیں
اس کے اوپر ترس آتا ہے کہ آج غریب
چھپراسی، غریب سپاہی، غریب کلرک،
غریب دوکاندار، غریب ریڑھی والا رکشا

[شری عبدلغنی]

کئی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ چھوٹے کسان جو تقریباً ۲۵ کروڑ ہیں اس دیش میں جن کی زمین ۱۰ ایکڑ سے بھی کم ہے - کئی تو ایسے ہیں جن کی زمین پانچ ایکڑ سے بھی کم ہے وہ ۲۵ کروڑ کسانوں کی بھلائی اس میں ہم نے دیکھی اور ہم نے کوآپریٹیو فارمنگ بنا کر یہ چیز قائم کی کیوں کہ اس میں ان کا بھلا ہے - اس کے لئے ہم نے پلان کیا لیکن نتیجہ کیا ہوا ؟

†[श्री अब्दुल गनी (पंजाब) : महोदया डिप्टी चेयरमैन, यह सुझाव जो हाऊस के सामने आया है इसमें बड़ी अहमियत है । इसका ताल्लुक न सिर्फ किसानों से है, बल्कि सारे देश की उन्नति इस पर निर्भर है ।

आज इस बात की चर्चा है कि रेवोल्यूशन हमारे दरवाजे पर बड़े ज़ोर से थपकियां दे रहा है और वो रवोल्यूशन क्यों आएगा, इसलिए कि देश इनके मसलों को, इनकी समस्याओं को हल नहीं कर सका । मैं उस वक्त नागपुर में मौजूद था । बहैसियत आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर होने के नाते, जिसमें यह को-आपरेटिव फार्मिंग की चर्चा हुई । मैं उन लोगों में था जो कि इसकी हिमायत करते थे, लेकिन साथ ही साथ अपने शकूक का इज़हार भी कि किस ढंग से इसको हमारे देश में सरकार बनाना चाहती है, जिस पर गौर किया । इससे पेश्तर कि मैं इस समस्या की ओर मुझे यह देखना है कि जब अंग्रेज गया तो हमारे देश की हालत क्या थी । हमें कितना विदेशों से मंगाना पड़ा और जब कि हम योजना पर योजनाए चलाए जाते हैं और यहां तक कि हाउस का जो खयालथा, सब तरफ से सहकारी खेती-बाड़ी पर जोरों से ताईद की गयी । तकरीबन तमाम पार्टियों ने इसकी बड़ी महिमा और बड़ी चर्चा की । अगर हम इस बात की चर्चा करें, बापू कहा करते थे कि ज्यादा आंकड़ें न बताओ, लेकिन आज की हुकूमत सारी चलती है वह आंकड़ों के जोर पर ही चलती है और प्लान करती है । अगर वो काबू न कर पाए हिन्दुस्तान में बच्चे ज्यादा पैदा न हों । कहते हैं कि ३० फी सदी, बाज़ लोग कहते हैं कि २५ फी सदी, हमारी आबादी बढ़ गयी है । ठीक है, आबादी बढ़ गयी होगी, बहन-भाइयों को तरस कुछ न आया होगा कि सरकार की कमजोरियों पर जिसके पास साधन नहीं है कि इतने ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएं और इतनी ही खुराक भी पैदा होती जाए । लेकिन बहरहाल कांग्रेस सरकार ने बड़ा दावा किया और यह कहा कि हमारी पैदावार देश में बड़े जोरों से बढ़ रही है और जिस वक्त यह कहा कि हम इतने सीड फार्म, इतने हम ट्यूबवेल लगा रहे हैं, कहीं भाखड़ा की चर्चा हुई, कहीं दामोदर वैली की चर्चा की गई, कहीं और डैम की चर्चा की गई लेकिन हालत क्या है । मैं ही नहीं देखता, आप भी देखते हैं । आप ही नहीं देखते, बल्कि सारा संसार ही देखता है । वो हिन्दुस्तान जो दूसरों के लिए, राम राज्य की बात नहीं करता, मैं चन्द्रगुप्त के जमाने की बात नहीं करता, मैं मुगल एम्पायर की बात करता हूं । मुगल एम्पायर की बात जब अंग्रेजों ने यहां दखल दिया इसकी बात करता हूं । इस समय जितने झूके लोग होते थे, वो गंगा में, प्यारी गंगा की वादी में आते, थे और अपने पेट की आग को बुझाते थे । लेकिन आज हालत क्या है ? क्या सोशलिज्म का दावादार मुल्क, वो मुल्क जो कहता है कि हम सोशलिज्म लाना चाहते हैं, इसके ऊपर तरस आता है कि आज एक गरीब चपड़ासी, गरीब सिपाही, गरीब क्लक, गरीब दुकानदार, गरीब रेड़ी वाला–रिक्शा वाला – तांगे वाला, आज जो भाव बम्बई में है ७० रुपये से ज्यादा में गन्दम बिक रही है । क्या वह समझता है

†[ ] English translation.

कि वह अच्छी तरह से अपनी जिन्दगी गुजर-बसर कर सकता है और अपने बच्चों का पेट पाल सकता है ? आज हम इस महंगाई के मुकाबले में कितना सरकारी मुलाजिमों को और भत्ता दे सकते हैं और महंगाई का एलाऊंस दे सकते हैं, जिससे देश के देव को, भूख के देव से बचा सकें । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज हालत इस पहली हालत से चाहे, वो को-आपरेटिव के हक में, जिनमें यहां पर चर्चा इस की वजह हो और मैं नहीं जानता, मैं महाबली मानता हूं स्वर्गीय श्री सरदार पटेल को, लेकिन मैं डाह्याभाई पटेल को ऐसा नहीं मानता कि वो इतने बड़े हनुमान हैं कि सब पार्टियां चाहे वो को-आपरेटिव फार्म हों वो सब की सब फेल हो जाएं, क्योंकि डाह्याभाई पटेल और इनकी स्वतन्त्र पार्टी जिनको जन्म लिए पीर-पीर आठ दिन हुए वो इतनी मजबूत हो गयी है कि बाकी सब पार्टियां चाहे चन्द्रशेखर की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, सोशलिस्ट की पार्टी हो वो सब फेल हो गयीं और इसके मुकाबले में कहां का तूफान आ गया कि इसमें सबको और आपको फेल कर दिया । जब आप इसकी तह में जायेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि यह योजना बहुत पहले नागपुर में प्रस्ताव पास करने से भी पहले की गयी थी और हमने यह कहा था कि छोटे किसान को जो तकरीबन २५ करोड़ हैं, इस देश में जिनकी जमीन १० एकड़ से भी कम है कई तो ऐसे हैं, जिनकी जमीन ५ एकड़ से भी कम है, वो २५ करोड़ किसानों की भलाई इसमें हमने देखी और हमने को-आपरेटिव फार्म को बना कर यह चीज कायम की; क्योंकि इसमें उनका भला है और इसलिए हमने प्लान किया । लेकिन नतीजा क्या हुआ ?]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ghani, it is five of the clock. You may continue your speech on another occasion.

SHRI ABDUL GHANI: Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 AM. on Monday.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 14th September, 1964.

GMGIPND—RS—660RS—22-11-64—550